▪ RNI No. : TNHIN/2013/5252 ▪ वर्ष - 13 ▪ अंक - 187 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- चेन्नई » सोमवार » 02-02-2026 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 'एप्सटीन फाइल' के मामले पर स्पष्टीकरण दें प्रधानमंत्री : कांग्रेस

6 धातुओं की दुनिया में अस्थिरता का खेल

7 भारतीय महिलाओं के अंदर 'सुपरपावर' होती है : रानी मुखर्जी

फर्स्ट टेक

यूक्रेन में रूस की सैन्य जीत दिखाई दे रही है : दिमित्री मेदवदेव

मॉस्को/भाषा। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने रविवार को कहा कि यूक्रेन में कई मापदंडों पर सैन्य विजय पहले से ही दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि आगे क्या होगा, इस बारे में सोचना भी आवश्यक है। मेदवदेव ने इस महीने के अंत में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के चार साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 'वास्तव में' इतिहास में एक शांति स्थापित करने वाले के रूप में दर्ज होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ''यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सैन्य विजय का तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है और यह कई मापदंडों पर दिखाई देता है।'' वह सरकारी समाचार एजेंसी तास और सैन्य चैनल वारगोंजो सहित कई मीडिया घरानों को दिए गए एक साक्षात्कार में अपनी बात रख रहे थे।

बोकोहराम का एक कमांडर और 10 उग्रवादी ढेर : नाइजीरिया की सेना

अबुजा/एपी। नाइजीरिया की सेना ने रविवार को कहा कि उसने देश के उत्तरपूर्वी हिस्से में रात के समय की गई छापेमारी में बोकोहराम के एक शीर्ष कमांडर और इस्लामी चरमपंथी समूह के 10 सदस्यों को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता सानी उबा ने एक बयान में कहा कि बोर्नो राज्य के सांबिसा जंगल में बोको हराम का कमांडर अबू खालिद उग्रवादी कृतियों को अंजाम देने वाला एक प्रमुख व्यक्ति था, जो सांबिसा क्षेत्र में संचालन और रसद का का काम देखता था। उबा ने बताया कि सैनिकों ने शनिवार रात बोर्नो राज्य के कोडुंगा क्षेत्र में बोको हराम के उग्रवादियों पर हमला किया और उनसे हथियार, खाद्य सामग्री और चिकित्सा आपूर्ति बरामद की।

यूपीआई लेनदेन जनवरी में 28.33 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर

नई दिल्ली/भाषा। देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिये होने वाला लेनदेन जनवरी में 28.33 लाख करोड़ रुपए के मूल्य और 21.70 अरब की संख्या के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई। एनपीसीआई ने बताया कि दिसंबर 2025 में लेनदेन का मूल्य 27.97 लाख करोड़ रुपए रहा था। मासिक आधार पर लेनदेन के मूल्य में 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में औसत दैनिक लेनदेन 70 करोड़ रहा जिसका औसत मूल्य 91,403 करोड़ रुपए था।

02-02-2026 सूर्यास्त 6:10 बजे | 03-02-2026 सूर्योदय 6:34 बजे

BSE	NSE
80,722.94	24,825.45
(-1,843.43)	(-593.45)

सोना	चांदी
16,535 रु.	320,000 रु.
(24 कैरेट) प्रति ग्राम	प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

लिहाज करो

तंत्र के शुभ मंत्र को ना,
फाड़ कर चिन्दा करो।
क्यों मरे को मारते हो,
स्वयं को जिन्दा करो।
सिर्फ वोटों के लिए,
ना आप यूं निंदा करो।
भाषणों में शब्द को,
ऐसे न शर्मिंदा करो।

केंद्रीय बजट 2026-27

लोकलुभावन फैसलों से दूरी, सुधार और निवेश पर जोर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

- 53.5 लाख करोड़ का बजट, निवेश और विकास पर फोकस
- एफएंडओ टैक्स बढ़ने से शेयर बाजार में तीखी गिरावट
- छोटे उद्योग, कृषि और पर्यटन बने प्राथमिकता क्षेत्र
- डेटा सेंटर को 20 साल की कर छूट, डिजिटल इंडिया को बल

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करते हुए लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज किया और आर्थिक सुधारों, पूंजीगत निवेश, विनिर्माण, कृषि तथा पर्यटन को विकास का आधार बनाने पर जोर दिया। कुल 53.5 लाख करोड़ रुपये के इस बजट को सरकार ने 'विकसित भारत' की दिशा में एक ठोस और दूरदर्शी कदम बताया है।

चुनावी वर्ष की पृष्ठभूमि के बावजूद बजट में राजकोषीय अनुशासन को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीति अपनाने का संकेत दिया है।

बजट पेश होने के बाद वायदा एवं विकल्प कारोबार पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाए जाने से शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी में करीब दो प्रतिशत की गिरावट देखी गई, हालांकि सरकार ने इसे सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम बताया।

सरकार ने आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.22 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जो अब तक का सर्वाधिक स्तर है। बुनियादी ढांचे, परिवहन, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश को रोजगार सृजन और मांग बढ़ाने का प्रमुख माध्यम माना गया है।

विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सात प्राथमिक क्षेत्रों—औषधि, सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज, रसायन, पूंजीगत वस्तुएं, वस्त्र और खेल सामग्री—में उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की गई है। छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई वृद्धि कोष प्रस्तावित किया गया है।

कृषि क्षेत्र में पारंपरिक खेती के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाली कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, ताकि ग्रामीण आय में वृद्धि हो सके। पर्यटन क्षेत्र के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरण-अनुकूल पर्वतीय मार्गों तथा 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास का प्रस्ताव रखा गया है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बजट में एक अहम घोषणा भारत से वैश्विक डेटा सेंटर सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों को 20 वर्षों तक कर छूट देने की है। इसके साथ ही विदेशी क्लाउड कंपनियों की संबंधित इकाइयों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की लागत पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

कर सुधारों के तहत सीमा शुल्क व्यवस्था को सरल किया गया है। 17 कैंसर दवाओं को सीमा शुल्क से मुक्त किया गया है और व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर शुल्क घटाया गया है। नया आयकर अधिनियम, 2025, एक अप्रैल से लागू होगा।

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में घोषित प्रमुख प्रावधान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 पेश किया। इस बजट भाषण के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं ---

- आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं।
- वायदा एवं विकल्प (एफ एंड ओ) सौदों पर लगने वाले प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) को बढ़ाकर क्रमशः 0.05 प्रतिशत और 0.15 प्रतिशत किया गया।
- विदेशी पर्यटन पैकेज की बिक्री पर 'स्रोत पर कर संग्रह' (टीसीएस) की दर को दो प्रतिशत किया गया।
- उदारीकृत धनप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विदेश में शिक्षा और चिकित्सा खर्च पर टीसीएस को भी दो प्रतिशत किया गया।
- नया आयकर अधिनियम, 2025 इस साल एक अप्रैल से लागू होगा, नियम और फॉर्म जल्द जारी होंगे।
- बिना ऑडिट वाले व्यवसायों के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की तारीख अगस्त 31 तक बढ़ाई गई।
- विदेशी कंपनियों को भारत के डेटा सेंटर से वैश्विक सेवाएं प्रदान करने पर 2047 तक मिलेगा 'कर अवकाश।'
- वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.3 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य, जो वित्त वर्ष 2025-26 के 4.4 प्रतिशत से कम है।
- जीडीपी में ऋण का अनुपात 56.1 प्रतिशत से घटाकर 55.6 प्रतिशत किया गया।
- वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल बजट का आकार 53.5 लाख करोड़ रुपए।
- सरकारी पूंजीगत व्यय को 11.11 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया।
- राज्यों को कर हिस्सेदारी के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित।
- शुद्ध कर संग्रह 28.7 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान।
- सकल बाजार उधारी 17.2 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान।
- बजट का 'तीन कर्त्तव्य' पर ध्यान, वृद्धि की रफ्तार तेज करना, आकांक्षाओं को पूरा करना, और सबका साथ, सबका विकास।
- सुधारों के 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' के तहत 350 से अधिक सुधार लागू।
- एसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए का वृद्धि कोष बनाने का प्रस्ताव, भविष्य के चैंपियन बनाने का लक्ष्य।
- सीमाशुल्क के लिए विश्वास-आधारित प्रणाली, पूर्व-निर्धारित कर निर्णय (एडवांस रुलिंग) की वैधता अवधि पांच वर्ष तक बढ़ाई गई।
- सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2047 तक बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने के लिए उच्चस्तरीय के गठन का प्रस्ताव।

बजट 'महत्वाकांक्षी', 'भविष्योन्मुखी' : प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को आम बजट 2026-27 को ''महत्वाकांक्षी'' और ''भविष्योन्मुखी'' बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत करेगा, क्योंकि देश के 140 करोड़ नागरिक इसके सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट नहीं हैं और राष्ट्र जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

बजट में भारत के वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई : राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को दावा किया कि केंद्रीय बजट में भारत के सामने मौजूद वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''युवाओं के पास नौकरी नहीं है, विनिर्माण गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है, किसान संकट में हैं, आसन्न वैश्विक झटके, सभी को नजरअंदाज कर दिया गया।'' उन्होंने दावा किया कि यह एक ऐसा बजट जिसमें चीजों को दुरुस्त करने के बजाय वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई।

बसों में आग

रविवार को रांची के खड़गढ़ा बस स्टैंड पर यात्री बसों में आग लगने के बाद अग्निशमन कर्मी आग बुझाने का प्रयास करते हुए।

प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जालंधर (पंजाब)/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा, आदमपुर किया और लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे पर सिविल टर्मिनल भवन का ऑनलाइन तरीके से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी अपराह्न लगभग तीन बजकर 45 मिनट पर आदमपुर हवाई अड्डे पहुंचे।

गुरु रविदास की 649वीं जयंती के मौके पर मोदी यहां डेरा सचखंड बल्लां भी गए।

इस बीच, मोदी ने लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया, जिससे पंजाब में बुनियादी विमानन ढांचे को और बढ़ावा मिलेगा।

रायकोट उपखंड के हलवारा स्थित भारतीय वायु सेना अड्डे पर विकसित इस टर्मिनल से क्षेत्र में हवाई संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होने और औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हवाई अड्डे की टर्मिनल भवन परियोजना को पंजाब सरकार और भारतीय विमानन प्राधिकरण के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में 54.67 करोड़ रुपए के परिव्यय से स्थापित किया गया है।

इस मौके पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और अन्य गणमान्य व्यक्ति लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे पर मौजूद थे।

रोहित शेट्टी के घर पर गोलीबारी, पांच लोग हिरासत में लिए गए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। फिल्मकार रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित आवास पर गोलीबारी के मामले मे पुणे में पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक जांच में इन लोगों के लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य और राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में आरोपी शुभम लोनकर से जुड़े होने के संकेत मिले हैं।

अधिकारियों के अनुसार, जूहू इलाके में स्थित नौ मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर शनिवार रात करीब 12:45 बजे कम से कम पांच गोलियां चलाई गईं। एक गोली इमारत में स्थित जिम के शीशे में जा लगी।

घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि घटना के समय शेट्टी अपने आवास पर मौजूद थे या नहीं।

गोलीबारी के बाद शेट्टी के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारी ने बताया कि स्थानीय पुलिस और अपराध शाखा की टीम मामले की जांच कर रही हैं। जूहू पुलिस और अपराध शाखा की टीम घटनास्थल पर पहुंचीं और जांच शुरू की।

पुलिस ने घटनाक्रम की कड़ी जोड़ने के लिए इमारत के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की पड़ताल की। फॉरेंसिक विज्ञान और बैलिस्टिक विशेषज्ञों की टीम भी साक्ष्य जुटाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचीं।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पुणे पुलिस के डीसीपी (जोन-3) संभाजी कदम ने बताया कि पांचों आरोपियों को वारजे मालवाड़ी थाने के पुलिसकर्मियों ने हिरासत में लिया।

हिरासत में लिए गए आरोपियों की पहचान करवे नगर के निवासी अमन मारोटे (27) व आदित्य गायकी (19) और धायरी के रहने वाले सिद्धार्थ येनपुरे (20), समर्थ पोमाजी (18) और स्वप्निल सकट (23) के रूप में हुई है।

ट्रंप ने किया दावा

भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा

न्यूयॉर्क/भाषा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने शनिवार को फ्लोरिडा के पाम बीच

जाते समय 'एयर फोर्स वन' में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी इस सवाल के जवाब में की कि क्या चीन वेनेजुएला को दिए गए कर्ज की भरपाई तेल आपूर्ति के बदले कर पाएगा। ट्रंप ने कहा, ''चीन का स्वागत है और वह तेल के मामले में एक बड़ा सौदा कर सकता है। हम चीन का स्वागत करते हैं। हम पहले ही एक सौदा कर चुके हैं। भारत आ रहा है और वह ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला का तेल खरीदेगा। हमने पहले ही यह सौदा कर लिया है, कम से कम इस सौदे की अवधारणा तो तय हो चुकी है।'' ट्रंप की इन टिप्पणियों पर नई दिल्ली की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने सैन्य कार्रवाई की धमकी देते हुए कहा

अगर अमेरिका युद्ध शुरू करता है, तो इस बार पूरा क्षेत्र इसकी चपेट में आ जाएगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

> हम न तो उकसाने वाले हैं और न ही किसी देश पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन ईरान पर जो कोई भी हमला करेगा या उसे परेशान करेगा, उसे ईरानी जनता कड़ा जवाब देगी।

दुबई/एपी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की धमकी पर पलटवार करते हुए रविवार को चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने हमला किया, तो पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय युद्ध भड़क सकता है।

अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और इससे जुड़े युद्धपोत फिलहाल अरब सागर में तैनात हैं, जिन्हें ट्रंप ने तेहरान में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बाद भेजा था।

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप सैन्य ताकत का उपयोग करेंगे या नहीं। उन्होंने कई बार कहा है कि ईरान बातचीत चाहता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा हल होते हुए देखना चाहते हैं।

हालांकि, खामेनेई ने राष्ट्रीय स्तर पर जारी विरोध प्रदर्शनों को तख्तापलट जैसा बताया और कहा कि इससे सरकार का रुख और कड़ा हो गया है। खबरों के अनुसार, विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से लाखों लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं।

ईरान में राजद्रोह के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान है। इससे यह चिंता फिर से बढ़ गई है कि तेहरान गिरफ्तार लोगों को सामूहिक रूप से फांसी देने जैसी कार्रवाई कर सकता है।

ईरान ने रविवार और सोमवार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य में सैन्य अभ्यास करने की योजना भी बनाई है। होर्मुज जलडमरूमध्य वह संकरा मार्ग है, जहां से बड़ी मात्रा में दुनियाभर में तेल की ढुलाई होती है।

ईरानी सरकारी टेलीविजन ने खामेनेई के हवाले से कहा, अमेरिकियों को यह समझ लेना चाहिए कि यदि वे युद्ध शुरू करते हैं, तो इस बार यह एक क्षेत्रीय युद्ध होगा।

खबर के अनुसार, खामेनेई ने कहा, हम न तो उकसाने वाले हैं और न ही किसी देश पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन ईरान पर जो कोई भी हमला करेगा या उसे परेशान करेगा, उसे ईरानी जनता कड़ा जवाब देगी।

खामनेई ने स्वीकार किया कि कुछ लोगों की आर्थिक समस्याएं वास्तविक थीं और इन्हीं कारणों से उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किए थे।

बजट में छोटे उद्योगों के साथ कृषि, पर्यटन क्षेत्रों पर जोर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार अल्पकालिक लाभ देने वाली लोकलुभावन घोषणाओं के बजाय दीर्घकालिक आर्थिक सुधारों की राह पर आगे बढ़ेगी। बजट में कृषि, पर्यटन, विनिर्माण, लघु उद्योग और डिजिटल अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखा गया है। इसे 'सुधार एक्सप्रेस' की निरंतरता के रूप में देखा जा रहा है।

शेयर बाजार पर बजट घोषणाओं का तत्काल असर : बजट में वायदा एवं विकल्प (एफ एंड ओ) कारोबार पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाए जाने के बाद शेयर बाजार में तेज बिकवाली देखने को मिली। निवेशकों की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण बीएसई सेंसेक्स करीब 1,547 अंक टूट गया, जबकि एनएसई निफ्टी में लगभग 495 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट मुख्य रूप से सट्टा कारोबार पर कर बोझ बढ़ने की प्रतिक्रिया है।

कुल बजट आकार और रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय : सरकार ने 53.5 लाख करोड़ रुपए के कुल बजट का प्रावधान किया है, जो अब तक के सबसे बड़े बजटों में से एक है। इसमें पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.22 लाख करोड़ रुपए किया गया है। सरकार का कहना है कि बुनियादी ढांचे में यह निवेश रोजगार सृजन के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को गति देगा और मध्यम अवधि में निजी निवेश को भी आकर्षित करेगा।

चुनावी माहौल के बावजूद राजकोषीय अनुशासन : पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित पांच राज्यों में आगामी चुनावों के बावजूद बजट में किसी भी तरह की बड़ी लोकलुभावन योजना की घोषणा नहीं की गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है, ताकि सार्वजनिक वित्त स्थिर रहे और दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती सुनिश्चित की जा सके।

सीमा शुल्क ढांचे में सरलीकरण और राहत : बजट में सीमा शुल्क प्रणाली को युक्तिसंगत बनाते हुए 17 कैंसर रोधी दवाओं को शुल्क से पूरी तरह मुक्त किया गया है। इसके अलावा 'बैगेज नियमों' में ढील दी गई है और व्यक्तिगत उपयोग की आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे आम यात्रियों को सीधी राहत मिलने की उम्मीद है।

सात प्राथमिक विनिर्माण क्षेत्रों पर विशेष फोकस : सरकार ने औषधि, सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज चुंबक, रसायन, पूंजीगत वस्तुएं, वस्त्र और खेल सामग्रीइन सात क्षेत्रों को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया है। इन क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण बढ़ाकर आयात निर्भरता कम करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि, पशुधन और मत्स्य पालन को बढ़ावा : बजट में पारंपरिक कृषि के साथ पशुधन, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाली कृषि गतिविधियों पर भी जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इन क्षेत्रों में निवेश से ग्रामीण आय में वृद्धि होगी व किसानों को वैकल्पिक आजीविका के अवसर मिलेंगे। जैव-

औषधि विनिर्माण के लिए 10,000 करोड़ रु. का निवेश प्रस्तावित किया गया है।

कपड़ा उद्योग के लिए एकीकृत विकास योजना : कपड़ा क्षेत्र के लिए एक समेकित कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य उत्पादन, निर्यात और रोजगार को एक साथ बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रोजगार सृजन को गति देने में सहायक माना जा रहा है।

पर्यटन क्षेत्र के लिए नई विकास रणनीति : पर्यटन को आर्थिक विकास का प्रमुख स्तंभ मानते हुए सरकार ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरण के अनुकूल पर्वतीय मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास से सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

लघु उद्यमों के लिए एसएमई ग्रोथ फंड : लघु एवं मध्यम उद्यमों को भविष्य के 'चैंपियन' के रूप में विकसित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई वृद्धि कोष प्रस्तावित किया गया है। चयनित मानदंडों के आधार पर इन उद्यमों को वित्तीय और नीतिगत सहायता दी जाएगी।

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच बजट : वित्त वर्ष 2026-27 का बजट ऐसे समय आया जब वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति शृंखला में बाधाएं और जिंस कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है। इसके बावजूद सरकार का कहना है कि घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है और मुद्रास्फीति में हालिया गिरावट से अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा।

राजकोषीय घाटा और ऋण प्रबंधन : सरकार ने अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को 4.3 प्रतिशत तक सीमित रखने और ऋण-जीडीपी अनुपात को घटाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बॉन्ड बाजार से 17.2 लाख करोड़ रुपए उधार लेने की योजना बनाई गई है।

प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया : प्रधानमंत्री ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को सशक्त आधार प्रदान करता है।

कर नीति में स्थिरता, निवेश पर जोर : हालांकि व्यक्तिगत आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन उद्योग और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कर अनुपालन को सरल बनाने वाले कई उपाय घोषित किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

औद्योगिक और तकनीकी पहल : बजट में बायोफार्मा केंद्र, सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा चरण, इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जा विनिर्माण व दुर्लभ खनिज गलियारों जैसी कई दीर्घकालिक औद्योगिक पहलों की घोषणा की गई है।

डेटा सेंटर और डिजिटल बुनियादी ढांचा : डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विदेशी डेटा सेंटर कंपनियों को 20 वर्षों तक कर छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। इससे भारत को वैश्विक डिजिटल सेवाओं का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।

एफ एंड ओ कारोबार पर कर बढ़ोतरी : वायदा और विकल्प कारोबार पर एसटीटी बढ़ाने का निर्णय सरकार के अनुसार बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी को नियंत्रित करने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।

टीसीएस और अन्य कर राहत : विदेशी पर्यटन पैकेज, विदेश शिक्षा और चिकित्सा खर्च पर टीसीएस घटाकर 2% किया है, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलने की संभावना है। नया आयकर अधिनियम, 2025 एक अप्रैल से लागू होगा।

'तीन कर्तव्यों' पर आधारित बजट दर्शन : बजट को आर्थिक वृद्धि, जन-आकांक्षाओं की पूर्ति और समावेशी विकासइन तीन स्तंभों पर आधारित बताया गया है। संरचनात्मक सुधार, मजबूत वित्तीय प्रणाली और आधुनिक तकनीक को विकास की कुंजी माना गया है।

बुनियादी ढांचा और परिवहन विस्तार : माल ढुलाई गलियारों, राष्ट्रीय जलमार्गों, तटीय परिवहन और समुद्री विमान निर्माण को बढ़ावा देकर लॉजिस्टिक्स लागत कम करने का लक्ष्य रखा गया है।

बजट: 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में स्थापित होंगी 'एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब'

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रमुख पहल 'इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज' के तत्वावधान में 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में 'कंटेंट क्रिएटर लैब' स्थापित करने में सहयोग देने का प्रस्ताव रखा है। सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र एक उभरता हुआ उद्योग है, जिसके लिए 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होने का अनुमान है। मैं 15,000 माध्यमिक स्कूलों व 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, मुंबई को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं। केंद्रीय बजट में सूचना व प्रसारण मंत्रालय को 4,551.94 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें से एक बड़ी राशि भारत के सार्वजनिक प्रसारक 'प्रसार भारती' के साथ-साथ एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग क्षेत्र में प्रतिभा विकास और सामुदायिक रेडियो के विस्तार को समर्थन देने के लिए निर्धारित की गई है।

रक्षा बजट बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपए किया गया, पूंजीगत व्यय में करीब 22 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली/भाषा। केंद्र सरकार ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7,84,678 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो पिछले वर्ष के आवंटन 6.81 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। सरकार का ध्यान खासकर चीन और पाकिस्तान से बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर सेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के परिप्रेक्ष्य में पूंजीगत खरीद के बजट समेत रक्षा आवंटन में की गई यह वृद्धि हमारी सेना को और अधिक मजबूत बनाने के संकल्प को प्रबल बनाएगी। कुल आवंटन में से 2,19,306 करोड़ रुपए सशस्त्र बलों के पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए, जिसमें मुख्य रूप से नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य उपकरण खरीदना शामिल है। यह पूंजीगत व्यय 2025-26 के बजट अनुमान की तुलना में 21.84 प्रतिशत अधिक है। पूंजीगत व्यय के तहत, 63,733 करोड़ रु. विमान और एयरो इंजन के लिए और 25,023 करोड़ रुपए नौसेना बेड़े के लिए आवंटित किए गए हैं।

कृषि क्षेत्र के लिए बहुभाषी एआई टूल 'भारत-विस्तार' को पेश करेगी सरकार

नई दिल्ली/भाषा। सरकार किसानों को अनुकूलित सलाह उपलब्ध कराने के लिए बहुभाषी कृत्रिम मेधा पर आधारित टूल 'भारत-विस्तार' पेश करेगी, जो एग्रीस्टैक पोर्टल और कृषि पद्धतियों पर आधारित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पैकेज को एकीकृत करेगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए आभासी रूप से एकीकृत प्रणाली 'भारत-विस्तार' (वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज)' को पेश किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा, ''मैं भारत-विस्तार पेश करने का प्रस्ताव करती हूं। यह एक बहुभाषी एआई टूल होगा जो एग्रीस्टैक पोर्टल और आईसीएआर के कृषि पद्धतियों पर आधारित पैकेज को एआई प्रणालियों के साथ एकीकृत करेगा। इससे खेती की उत्पादकता बढ़ेगी, किसानों को बेहतर फैसले लेने में मदद मिलेगी और विशिष्ट सलाह के जरिये जोखिम को कम किया जा सकेगा।'' एग्रीस्टैक पोर्टल किसानों के लिए डिजिटल सेवाओं का एक नेटवर्क हैं जिनमें खेती, बीज, सिंचाई, सब्सिडी और मौसम संबंधी जानकारी जैसी सेवाएं शामिल होती हैं।

सीतारमण ने संशोधित आयकर रिटर्न जमा करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव किया

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर से 31 मार्च करने का प्रस्ताव किया। मामूली शुल्क के भुगतान के साथ आयकरदाता इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। सीतारमण ने इसके साथ उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के मामले में लगने वाले स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की दर को पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव किया। विदेश यात्रा पैकेज की बिक्री पर लगने वाले टीसीएस की दर को पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने की घोषणा की गई। यह दर पहले 20 प्रतिशत थी।

उन्होंने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में छोटे करदाताओं के लिए नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया का भी प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजा को कर से छूट देने के प्रस्ताव की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि आयकर अधिनियम, 2025 एक अप्रैल से लागू होगा और इसके नियम एवं कर रिटर्न फॉर्म जल्दी ही अधिसूचित किए जाएंगे। एक अप्रैल से आयकर अधिनियम, 2025 लागू हो जाएगा, जो छह दशक पुराने कर कानून का स्थान लेगा। 2026-27 के बजट में कर कानूनों में किए गए बदलावों को नए कानून में शामिल किया जाएगा।

85 मिनट के भाषण में सीतारमण ने इस बार नहीं किया किसी कवि और कविता का उल्लेख

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में अपना लगातार नौवां बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने अपने गृह राज्य तमिलनाडु की परंपरागत बुनाई का सम्मान करते हुए सुनहरे चेक और कॉफी ब्राउन रंग की किनारी वाली बैंगनी रंग की कांजीवरम साड़ी पहनी थी जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सीतारमण के लगभग 85 मिनट के बजट भाषण को 'ऐतिहासिक और भविष्योन्मुखी' बताया। भाषण की शुरुआत गुरु रविदास को श्रद्धांजलि देते हुए और माघ पूर्णिमा के उल्लेख के साथ हुई। हालांकि, वित्त मंत्री के इस बार के बजट भाषण में किसी तरह की कविता या तमिल कवि तिरुवल्लुवर और कन्नड संत बसवन्ना आदि का संदर्भ नहीं दिया गया जिनका उनके पहले के बजट भाषणों में उल्लेख रहा है। इस बार के भाषण में वित्त मंत्री का पूरा ध्यान निवेश, विकास पर रहा और चुनावी राज्यों का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं हुआ।

भाषण के अंत में, केरल के कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा किया। उनका दावा था कि वित्त मंत्री ने उनके राज्य की अनदेखी की है, जहां अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं। अपनी बात रखते हुए सीतारमण ने कहा: सीतारमण ने कहा, ''प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने निर्णायक और सतत रूप से अनिश्चितता के बजाय कार्रवाई, बयानबाजी के बजाय सुधार और लोकलुभावनवाद के बजाय लोगों को चुना है।'' इस दौरान निचले सदन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समेत सत्ता पक्ष के सदस्य हर कुछ मिनट में मेजें थपथपा रहे थे, वहीं विपक्षी सदस्य अप्रभावित दिखे। यह पहला बजट था जिसे वित्त मंत्रालय के नए कार्यालय 'कर्तव्य भवन' (पूर्व में नॉर्थ ब्लॉक) में तैयार किया गया था। सदन की बैठक शुरू होने से पहले सांसद एक-दूसरे को बधाई देते नजर आए। भाजपा सांसद राजकुमार चाहर को अन्य सांसदों के साथ सेल्फी लेते देखा गया, जबकि द्रमुक नेता कनिमोई को गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से संक्षिप्त बातचीत करते हुए देखा गया। कई सदस्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) की सांसद सुप्रिया सुले के पास महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। अजित पवार का 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। सुप्रिया उनकी चचेरी बहन हैं। प्रियंका गांधी वाद्रा, अखिलेश यादव, हिबी इडन, तारिक अनवर, एन के प्रेमचंद्रन और मीसा भारती सहित कई नेताओं को सुले से पास जाकर उनसे बात करते हुए देखा गया।

आर्थिक राजनीतिक दूरदर्शिता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता बजट : कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने रविवार को केंद्रीय बजट को ''थकी और रिटायर हो चुकी सरकार का बजट'' करार दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण तथा बजट, आर्थिक रणनीति और आर्थिक राजनीतिक दूरदर्शिता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि केंद्रीय बजट में भारत के सामने मौजूद वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''युवाओं के पास नौकरी नहीं है, विनिर्माण गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है, किसान संकट में हैं, आसन्न वैश्विक झटके, सभी को नजरअंदाज कर दिया गया।'' कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्रीय बजट को लेकर नरेन्द्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इस सरकार के पास नीति, दृष्टि, समाधान और राजनीतिक इच्छा-शक्ति नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वंचित वर्गों के लिए कोई सहायता नहीं दी गई और किसानों की भी उपेक्षा हुई है। खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''मोदी सरकार के पास अब नए विचारों की कमी दिखती है। बजट-2026 भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का एक भी समाधान नहीं देता। 'मिशन मोड' अब 'चैलेंज रूट' बन गया है। 'सुधार एक्सप्रेस' शायद ही कभी किसी 'सुधार' जंक्शन पर रुकती है।'' उन्होंने दावा किया कि अब कोई नीति-दृष्टि नहीं है और कोई राजनीतिक इच्छा-शक्ति भी नहीं है। खरगे ने आरोप लगाया, ''यह एक थकी हुई और रिटायर हो चुकी

सरकार का बजट है। पहले तो यह पैसा नहीं देना चाहती और ऊपर से मिले बजट को भी खर्च नहीं करती।''

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कटाक्ष किया कि सीतारमण ने या तो आर्थिक सर्वेक्षण को नहीं पढ़ा या फिर उसे जानबूझकर दरकिनार कर दिया। चिदंबरम ने कहा, ''आज संसद में वित्त मंत्री के भाषण में जो कुछ सुनने को मिला, उससे अर्थशास्त्र का हर छात्र अवश्य ही स्तब्ध रह गया होगा। बजट केवल वार्षिक राजस्व और व्यय का बयान भर नहीं होता। मौजूदा परिस्थितियों में बजट भाषण को उन

वित्त मंत्री सीतारमण ने राहुल पर किया पलटवार, देश की आर्थिक बुनियाद को बताया मजबूत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत है और बजट समाज के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करता है।

सीतारमण ने कहा, ''मुझे नहीं पता कि (राहुल) गांधी किन चीजों को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था और उसकी बुनियाद मजबूत है। वैश्विक अनिश्चितता हमारे कई क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है, जिनके लिए हमने लघु एवं मध्यम उद्यमों, वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग... किसानों और महिला उद्यमियों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।'' उन्होंने बजट के बाद मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि सरकार इन तरीकों से आम लोगों तक पहुंच रही है और उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित कर रही है। वित्त मंत्री लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा 'एक्स' पर एक पोस्ट में की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रही थीं। इससे पहले गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''युवाओं के पास नौकरी नहीं है, विनिर्माण गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है, किसान संकट में हैं, आसन्न वैश्विक झटके, सभी को नजरअंदाज कर दिया गया।'' उन्होंने दावा किया कि यह एक ऐसा बजट, जिसमें चीजों को दुरुस्त करने के बजाय वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई।

प्रमुख चुनौतियों पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण पेश करना चाहिए, जिनका जिक्र कुछ दिन पहले जारी आर्थिक समीक्षा 2025-26 में किया गया था।'' कांग्रेस नेता ने कहा, ''बजट भाषण और बजट, आर्थिक रणनीति और आर्थिक राजनीतिक दूरदर्शिता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते।'' पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वित्त मंत्री का बजट भाषण पारदर्शी नहीं रहा और इसमें प्रमुख कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन की जानकारी नहीं दी गई। रमेश ने पोस्ट किया, ''(बजट संबंधी) दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन करना अभी बाकी है, फिर भी 90 मिनट (के भाषण के) बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि बजट को लेकर जो उम्मीदें की गई थीं, उन पर यह पूरी तरह खरा नहीं उतरता। यह पूरी तरह से फीका और निराशाजनक रहा।''

बजट में विकसित भारत की यात्रा के केंद्र में रखा गया है अवसंरचना को: गडकरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में अवसंरचना को विकसित भारत 2047 की ओर देश की यात्रा के केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया।

गडकरी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''संपर्क, विनिर्माण की गहराई और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट तरीके से ध्यान देने के साथ, बजट में विश्वस्तरीय, भविष्य के लिए तैयार अवसंरचना बनाने के लिए एक निर्णायक कदम रेखांकित किया गया है।'' उन्होंने कहा कि बजट में घोषित पहल एक स्पष्ट दृष्टिकोण दिखाती हैं कि बुनियादी ढांचा सिर्फ भौतिक परिसंपत्ति के तौर पर नहीं, बल्कि लचीलापन, अवसर और ग्लोबल प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने वाला है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि 2026-27 के बजट में किसानों, युवाओं और एमएसएमई क्षेत्र पर केंद्रित एक निर्णायक रोडमैप प्रस्तुत किया गया है, जो भारत के आगे बढ़ने के साथ-साथ समावेशी विकास, नवाचार और पूंजी निवेश की नींव को मजबूत करेगा।

लेनदेन कर वायदा सौदों पर 150 प्रतिशत, विकल्प पर 50 प्रतिशत बढ़ा, बाजार टूटा

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट में वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) खंड में अत्यधिक सट्टेबाजी रोकने के लिए डेरिवेटिव्स पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि, शेयर बाजार को यह घोषणा पसंद नहीं आई। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि वायदा अनुबंधों पर एसटीटी को वर्तमान के 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया जाएगा। साथ ही विकल्प सौदों में प्रीमियम और विकल्प के उपयोग पर एसटीटी को बढ़ाकर 0.15% किया जाएगा जो वर्तमान में क्रमशः 0.1 और 0.125% है। उन्होंने यह भी कहा कि शेयरों की पुनर्खरीद से प्राप्त राशि पर सभी प्रकार के शेयरधारकों के लिए पूंजीगत लाभ कर लागू किया जाएगा। एफएंडओ खंड में एसटीटी बढ़ाने का मकसद मुख्य रूप से उच्च-मात्रा वाले डेरिवेटिव सौदों को नियंत्रित करना है, जबकि नकद इक्विटी बाजार पर इसका असर सीमित रहेगा। यह कदम अत्यधिक सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने और अधिक संतुलित बाजार संरचना बनाए रखने में मदद कर सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु रविदास को दी श्रद्धांजलि, डेरा सचखंड बल्लां के कार्यों की सराहना की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जालंधर (पंजाब)/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को यहां डेरा सचखंड बल्लां गए और समाज सुधारक तथा कवि के रूप में याद किए जाने वाले संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

संप्रदाय के प्रमुख संत निरंजन दास को 25 जनवरी को पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई थी। इसके कुछ दिन बाद मोदी ने यह यात्रा की।

जालंधर के बल्लां में स्थित डेरा सचखंड, राज्य में रविदासिया समुदाय का सबसे बड़ा डेरा है।

गुरु रविदास जयंती और माघ पूर्णिमा के मौके पर लोगों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ''मैं पंजाब दी इस धरती नू नमन करदा हां।'' लोकसभा में उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह निर्वाचन क्षेत्र गुरु रविदास की जन्मभूमि भी है। उन्होंने कहा, ''वाराणसी के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे वहां से सांसद के रूप में इस जगह की सेवा करने का अवसर मिला।'' उन्होंने कहा, ''हम गुरु रविदास से प्रेरणा लेते हैं।''

मोदी ने कहा, ''संत रविदास के आशीर्वाद से, मुझे विश्वास है कि हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।''

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सामाजिक सेवा के क्षेत्र में डेरा सचखंड बल्लां के कार्य प्रशंसनीय रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर के बजट में पुराने श्रीनगर के लिए अलग से प्रावधान किए जाएं : महबूबा मुफ्ती

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

श्रीनगर/भाषा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा अगले वित्त वर्ष के लिए पेश किए जाने वाले बजट में पुराने श्रीनगर शहर के विकास से अलग से प्रावधान किया जाना चाहिए। श्रीनगर के पुराने इलाके को 'शहर-ए-खास' के नाम से भी जाना जाता है।

जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के संबोधन के साथ शुरू होगा। केंद्र शासित प्रदेश के वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला छह फरवरी को वार्षिक बजट पेश करेंगे।

महबूबा ने श्रीनगर के बाबादेम्ब-खानयार इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ''शहर-ए-खास की अपनी समस्याएं हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एक अलग बजटीय प्रावधान होना चाहिए।''

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर-ए-खास में अधिकतर लोग सामान्य वर्ग में आते हैं और उन्हें सरकारी नौकरियों या अन्य संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। महबूबा ने कहा, ''अधिकतर लोग या तो हस्तशिल्प से जुड़े हैं या पर्यटन से। मशीन से बने उत्पादों के कारण हस्तशिल्प खतरे में है, जिसके परिणामस्वरूप कारीगरों की आय में कमी आई है।''

महबूबा ने रविवार को पीडीपी के संवाद कार्यक्रम में अपनी बात रखने वाले युवा लड़के-लड़कियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 'जेन जेड' (उन लोगों को कहा जाता है जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है) ने यह साबित कर दिया है कि उन्हें विभिन्न मुद्दों की जानकारी है, जो पिछली पीढ़ियों के पास शायद नहीं थी।

पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि संवादात्मक सत्र को मीडिया की नजरों से दूर रखा गया क्योंकि लोग कैमरों की मौजूदगी में खुलकर बोलने से कतराते हैं। उन्होंने कहा, ''वे इस बात से डरते हैं कि अगर वे अपने दिल की बात कहेंगे तो उन्हें सरकार से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दुर्भाग्य से, सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगाना चाहती है।''

बेहद निराशाजनक है केंद्रीय बजट : मुख्यमंत्री स्टालिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु की 'अनदेखी करने' को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने रविवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट राज्य के लिए बेहद निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि बजट में तमिलनाडु के हितों की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी गयी है तथा गरीबों, महिलाओं, किसानों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने यहां एक बयान में कहा, ''तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की दहलीज पर है, ऐसे में हमें उम्मीद थी कि कम से कम इस साल तो राज्य केंद्र की भाजपा सरकार की नजरों में आएगा और हमारी आवाज उस तक पहुंचेगी। हालांकि, इस साल भी भाजपा सरकार ने सिर्फ निराशा ही दी है।'' उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु समेत विभिन्न राज्यों द्वारा कुल कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग को एक बार फिर 'नजरअंदाज' कर दिया गया है। उन्होंने कहा, ''यह घोषणा निराशाजनक है कि राज्यों के लिए राजस्व बंटवारा 41 प्रतिशत पर ही रहेगा।''

तमिलनाडु के नेताओं ने केंद्रीय बजट पर अलग-अलग राय जाहिर की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के नेताओं ने राज्य की वित्तीय स्थिति और विकास पर केंद्रीय बजट के प्रभाव को लेकर रविवार को अलग-अलग राय जाहिर की। भाजपा और उसके सहयोगियों ने जहां बजट को राज्य के औद्योगिक ढांचे और अवसंरचना के विकास के लिए एक रोडमैप के रूप में सराहा, वहीं विपक्ष ने इसे कृषि समुदाय एवं उद्य प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए अवसर चूक जाना करार दिया।

भाजपा की वरिष्ठ नेता तमिलिसाई सौंदरराजन ने विशाल अवसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से तमिलनाडु को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की। उन्होंने संवाददाताओं के साथ बातचीत में दुर्लभ खनिज गलियारे' और चेन्नई को हैदराबाद और बेंगलपरु से जोड़ने वाली हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी के महत्व पर प्रकाश डाला। सौंदरराजन ने कहा, प्रधानमंत्री उन लोगों की तरह नहीं हैं, जो चुनाव नजदीक आने पर ही योजनाओं की घोषणा करते हैं। उन्होंने लगातार धनराशि आवंटित की है, जिसमें तमिलनाडु के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपये भी शामिल हैंय

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की आलोचनाओं का जवाब देते हुए सौंदरराजन ने दावा किया कि बजट समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाता है। उन्होंने इस सिलसिले में विशेष रूप से प्रत्येक जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों की स्थापना और काजू एवं नारियल किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहनों का जिक्र किया। सौंदरराजन ने कहा, बतौर डॉक्टर मैं चिकित्सा पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने तथा कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर करों में छूट से विशेष रूप से खुश हूं। यह युवाओं और भविष्य के लिए बजट है।

पीएमके अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदास ने पूंजीगत व्यय 10 प्रतिशत बढ़ाकर 12.20 लाख करोड़ रुपये किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देश भर में रोजगार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने विशेष रूप से आदिचनल्लूर में एक सांस्कृतिक केंद्र को शामिल करने तथा पुलिकट झील और पोधिगई पहाड़ियों के लिए पर्यटन विकास परियोजनाओं की सराहना की। हालांकि, रामदास ने राजस्व बंटवारे पर अफसोस के साथ कहा, कृषि के लिए आवंटन में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन यह निराशाजनक है कि केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 41 प्रतिशत पर ही बना हुआ है। हम सरकार से इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का आग्रह करते हैं।'' वहीं, एमएनएम के संस्थापक कमल हासन ने केंद्र सरकार पर राज्य की महत्वपूर्ण विकास आवश्यकताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। हासन ने 'एक्स' पर लिखा, ''आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को केंद्रीय बजट में निरंतर समर्थन मिलना चाहिए, न कि केवल चुनाव पूर्व पुरस्कार। सौभाग्य से, तमिलनाडु की बारी 2026 में आएगी।''

बजट में निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के लिए दुर्लभ खनिज गलियारे की घोषणा की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट में चेन्नई के लिए हाई स्पीड रेल लिंक, पश्चिमी घाट के पोधिगई मलाई में पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ पर्वतीय मार्ग और एक दुर्लभ 'खनिज गलियारे' समेत तमिलनाडु के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने पुलिकट झील के किनारे पक्षी अवलोकन पथों का निर्माण और आदिचनल्लूर के पुरातात्विक स्थल को एक जीवंत, अनुभव जन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने जैसी अन्य घोषणाएं भी कीं।

मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए, हम शहरों के बीच सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेंगे जो विकास को जोड़ने वाले 'कनेक्टर' के रूप में काम करेंगे तथा हैदराबाद-चेन्नई और चेन्नई-बेंगलूरु उनमें शामिल होंगे।'' उन्होंने कहा, रेयर अर्थ पर्मानेंट मैग्नेट लिए एक योजना नवंबर 2025 में शुरू की गई थी। अब हम खनिज समृद्ध राज्यों-- ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दुर्लभ खनिज गलियारे स्थापित करने में सहायता देने का प्रस्ताव करते हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में विश्व स्तरीय 'ट्रेकिंग और हाइकिंग' अनुभव प्रदान करने की क्षमता और अवसर मौजूद हैं इसलिए, पश्चिमी घाट के पोधिगई मलाई में पर्यावरण के अनुकूल पर्वतीय मार्ग विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि साथ ही, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के किनारे पक्षी अवलोकन मार्ग भी विकसित किए जाएंगे।

हाई-स्पीड रेल, एसएमई के लिए उठाए गए कदमों से तमिलनाडु को होगा लाभ : अन्नाद्रमुक

चेन्नई। अन्नाद्रमुक महासचिव ई. के. पलानीस्वामी ने रविवार को केंद्रीय बजट के प्रस्तावों की सराहना की और कहा कि इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और तमिलनाडु को कई योजनाओं से फायदा होगा। नेता प्रतिपक्ष पलानीस्वामी ने कुछ विशिष्ट पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे तमिलनाडु के वस्त्र उद्योग केंद्रों जैसे तिरुप्पुर और करूर को लाभ मिलेगा और चेन्नई से जुड़ीं हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर जैसी योजनाओं से बड़े बदलाव होंगे।

अन्नाद्रमुक के शीर्ष नेता ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपये की एसएमई विकास निधि और सूक्ष्म उद्योगों की मदद के लिए 2,000 करोड़ रुपये का टॉप-अप आत्मनिर्भर भारत कोष तमिलनाडु को लाभान्वित करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने बजट में आयुर्वेद को महत्व देने का स्वागत किया।

बजट घोषणाओं से औद्योगिक विकास में तेजी आएगी : केंद्रीय मंत्री मुरुगन

चेन्नई। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने रविवार को कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट परिवर्तनकारी है तथा इससे औद्योगिक विकास में तेजी आएगी व देश को लचीले और विकसित भारत की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। मुरुगन ने बताया कि रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को मजबूत करने के लिए केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारमण ने बजट 2026 में कई परिवर्तनकारी पहलों का प्रस्ताव रखा है, जिनमें बायोफार्मा शक्ति, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में समर्पित दुर्लभ खनिज गलियारे शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में केंद्रीय राज्यमंत्री मुरुगन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ये उपाय औद्योगिक विकास को गति देंगे, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देंगे और भारत को एक लचीले व विकसित भारत की ओर अग्रसर करेंगे।

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रंगासामी ने केंद्रीय बजट को 'सबसे प्रगतिशील और विकासोन्मुखी' बताया

पुडुचेरी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 को सबसे प्रगतिशील और विकासोन्मुखी बताते हुए उसकी सराहना की। केंद्र शासित प्रदेश में एआईएनआरसी-भाजपा गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे रंगासामी ने कहा कि बजट अत्यंत प्रगतिशील और हर क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है। देश की अर्थव्यवस्था का विकास, रोजगार के अवसर, महिलाओं के विकास को बढ़ावा देना और उनके लिए अवसर उपलब्ध कराना तथा राष्ट्रव्यापी औद्योगिक विकास को बजट में महत्व दिया गया है। बजट की दीर्घकालिक योजना और व्यापक एवं समावेशी प्रकृति राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित करेगी। कुल मिलाकर बजट प्रशंसनीय है और देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाकर विकास के पथ पर अग्रसर करेगा।

चुनावी वर्ष में भी वित्त मंत्री सीतारमण ने तमिलनाडु को कुछ नहीं दिया : द्रमुक

चेन्नई। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक ने रविवार को आरोप लगाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में राज्य को एक बार फिर कुछ नहीं दिया है। द्रमुक ने बजट को ''दिशाहीन'' करार दिया है।

केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए द्रमुक प्रवक्ता के. रविंद्रन ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहां के लोगों की उम्मीदें अलग हैं, लेकिन जब हम पूरे बजट को देखते हैं तो उसमें लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) समेत किसी भी क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं है।

उन्होंने कहा, ''बजट का कोई उद्देश्य या लक्ष्य नहीं है और संक्षेप में कहें तो यह दिशाहीन है।'' उन्होंने आरोप लगाया कि बजट ने देश की जनता के बीच समग्र चिंता पैदा कर दी है, लेकिन इससे यह भी स्पष्ट रूप से पता चलता है कि तमिलनाडु में चुनाव प्रस्तावित होने के बावजूद केंद्र सरकार ने दक्षिणी राज्य पर जरा भी ध्यान नहीं दिया है। द्रमुक प्रवक्ता ने कहा कि यहां तक कि विशेषज्ञ भी बजट में कुछ ठोस नहीं देख पा रहे हैं और शेयर बाजार धराशायी हो गया है।

न्यायमूर्ति स्वामीनाथन के खिलाफ टिप्पणी के लिए मामले दर्ज : तमिलनाडु के डीजीपी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नई दिल्ली। तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि मदुरै की तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम' जलाने की अनुमति देने संबंधी आदेश के बाद मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी. आर. स्वामीनाथन के विरुद्ध कथित रूप से जाति एवं धर्म के आधार पर मानहानिकारक टिप्पणियां करने वाले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की है और मामले दर्ज किए गए हैं।

शीर्ष अदालत में दायर एक शपथपत्र में डीजीपी जी. वेंकटरमण ने यह भी कहा कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों को पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि ऐसी कोई भी पुस्तक प्रकाशित या प्रसारित न होने दी जाए जिसमें अदालत/न्यायाधीश की छवि धूमिल करने वाले चित्रात्मक निरूपण, बयान, कार्टून या इसी प्रकार की सामग्री हो। उन्होंने कहा, ''विनम्रतापूर्वक यह बताया जाता है कि ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने सोशल मीडिया मंचों-एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, व्हॉट्सऐप और अन्य डिजिटल मंचों-पर मानहानिकारक, अपमानजनक और अदालत की गरिमा पर आघात करने वाले पोस्ट के व्यापक प्रसार से जुड़े याचिकाकर्ता के आरोपों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की है।'' डीजीपी ने अदालत से कहा, ''ग्रेटर चेन्नई पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा के अंतर्गत साइबर अपराध प्रकोष्ठ ने त्वरित कार्रवाई की और याचिका को उपयुक्त पंजीकरण संख्या आवंटित की। चूंकि याचिका में सोशल मीडिया पर उन पोस्ट और अकाउंट का विवरण नहीं दिया गया, जिन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है, इसलिए साइबर अपराध प्रकोष्ठ ने ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट/सामग्री की जांच कर सोशल मीडिया मंचों पर तुरंत कार्रवाई की और तदनुसार एक्स' (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, यूट्यूब और अन्य मंचों पर नौ सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की।''

ये अभ्यावेदन अधिवक्ता जी. एस. मणि की याचिका के जवाब में पेश किए गए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कम्युनिस्ट दलों समेत सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) समर्थित दलों तथा कुछ व्यक्तियों एवं वकीलों ने चेन्नई और मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय परिसर के भीतर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध प्रदर्शन किए और न्यायमूर्ति स्वामीनाथन के खिलाफ अत्यंत अवमाननापूर्ण टिप्पणियां कीं। उच्चतम न्यायालय ने 28 जनवरी को मणि की याचिका पर राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक, चेन्नई पुलिस आयुक्त और अन्य को नोटिस जारी किए थे। उसने राज्य सरकार को मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था और मामले की सुनवाई के लिए दो फरवरी की तारीख तय की थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि जाति और धर्म पर आधारित ''मानहानिकारक टिप्पणियां'' सामाजिक सद्भाव एवं कानून व्यवस्था को बिगाड़ने और सांप्रदायिक अशांति को भड़काने के इरादे से की गई थीं।

न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने एक दिसंबर, 2025 को उन रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया था जिनमें एक दरगाह के निकट तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित पत्थर के दीप स्तंभ 'दीपथून' पर कार्तिकई दीपम् को प्रज्वलित करने के लिए उचित व्यवस्था करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। जब आदेश का पालन नहीं हुआ तो न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने तीन दिसंबर को एक और आदेश पारित किया जिसमें श्रद्धालुओं को स्वयं दीपक जलाने की अनुमति दी गई और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख किया।

केंद्रीय बजट देश की संप्रभुता और विकास पर केंद्रित : येडीयुरप्पा

बेंगलूरु। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)के वरिष्ठ नेता बी एस येडीयुरप्पा ने रविवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गए केंद्रीय बजट में देश की संप्रभुता और विकास दोनों समाहित हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य भाजपा नेताओं ने बजट को समावेशी बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य देश का सर्वांगीण विकास करना है।

येडीयुरप्पा ने कहा, ''यह बजट देश की संप्रभुता और विकास को समाहित करता है। यह बजट भारत की संप्रभुता और एकता को बनाए रखने में सफल रहा है। इसने देश के प्राचीन स्थलों के विकास को महत्व दिया है।'' उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि यह बजट समावेशी है और ''सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास'' के आदर्श वाक्य के अनुरूप है। येडीयुरप्पा ने बजट में की गई विभिन्न घोषणाओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसमें किसानों की आय दोगुनी करने, मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत करने, जलाशयों और मीठे पानी की झीलों का विकास करने, उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने, भारतीय काजू और नारियल को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करने, भारतीय चंदन पारिस्थितिकी तंत्र की प्रतिष्ठा को बहाल करने, प्रमुख शहरों को हाई-स्पीड रेल संपर्क प्रदान करने आदि पर केंद्रित है।

भाजपा की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष विजयेंद्र येडीयुरप्पा ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में युवाओं को प्राथमिकता देने वाले स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा, ''तीन कर्तव्यों आर्थिक विकास में तेजी लाना, जन-केंद्रित विकास और क्षमता निर्माण और सभी के लिए अवसरों तक समावेशी पहुंच द्वारा निर्देशित यह बजट 2047 तक विकसित भारत की यात्रा में युवाओं को सशक्त बनाने, रोजगार को बढ़ावा देने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक निर्णायक रोडमैप है।''

उन्होंने कहा, ''बेंगलूरु-चेन्नई और हैदराबाद-बेंगलूरु हाईस्पीड ट्रेन कॉरिडोर से कर्नाटक को काफी लाभ होगा, क्योंकि इससे संपर्क मजबूत होगा, आवागमन में सुधार होगा और सतत विकास को समर्थन मिलेगा, साथ ही राज्य की आर्थिक और बुनियादी ढांचागत गति में भी वृद्धि होगी।'' राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक आर अशोक ने कहा कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत की दिशा में एक दूरदर्शी, संतुलित और प्रगतिशील रोडमैप का प्रतिनिधित्व करता है।

स्वागत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्त्तव्य पथ पर शानदार प्रदर्शन करते हुए कर्नाटक और गोवा के एनसीसी निदेशालय की आरडीसी टुकड़ी ने 2025-26 के लिए सर्वश्रेष्ठ एनसीसी निदेशालय का प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री ध्वज प्राप्त किया। रविवार को बेंगलूरु आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जिसके बाद बेंगलूरु की प्रमुख सड़कों पर एक भव्य विजय रैली निकाली गई। लगातार दूसरी जीत स्टाफ, कैडेटों के सामूहिक प्रयास और समर्पण तथा कर्नाटक राज्य सरकार के सहयोग का प्रमाण है।

केंद्रीय बजट निराशाजनक, इसमें दूरदर्शिता की कमी है : सिद्दरामय्या

कलबुर्गी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट को ''निराशाजनक'' बताते हुए रविवार को कहा कि इसमें ''दूरदर्शिता की कमी'' है। सिद्दरामय्या ने यह भी दावा किया कि कर्नाटक के साथ बड़ा ''अन्याय'' हुआ है।

उन्होंने कहा, ''यह बजट निराशाजनक है और इसमें दूरदर्शिता की कमी है। इसमें सिर्फ बयानबाजी है।'' सिद्दरामय्या ने यहां पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा, कर्नाटक को कुछ नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, पूरे दक्षिण भारत को बजट में कुछ नहीं मिला है। बजट में कर्नाटक को सिर्फ 'चोम्बू' (एक खाली छोटा, गोल पानी का पात्र) दिया गया है।'' उन्होंने कहा, ''पिछले पांच वर्षों में कर्नाटक के बारे में मुख्य रूप से केवल दो ही चीजों का उल्लेख हुआ है : बेंगलूरु-चेन्नई और हैदराबाद-बेंगलूरु हाई-स्पीड रेल कॉरिडो। इससे कर्नाटक को कोई लाभ नहीं होगा। यह तेलंगाना और तमिलनाडु के लिए अधिक लाभदायक है। हमने बेंगलूरु-मुंबई, बेंगलूरु-मंगलूरु और बेंगलूरु-पुणे हाई-स्पीड रेल की मांग की थी।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट में 'विकसित भारत' की बात की है। उन्होंने कहा, ''ये सिर्फ बातें हैं, काम नहीं।'' उन्होंने कहा कि राज्य की सिंचाई परियोजनाओं का कोई उल्लेख नहीं है।

केंद्रीय बजट से कर्नाटक को कोई फायदा नहीं हुआ : शिवकुमार

बेंगलूरु। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने रविवार को कहा कि संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट से राज्य को कोई लाभ नहीं हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया। शिवकुमार ने हालांकि कहा कि उन्होंने अभी तक बजट का विस्तार से अध्ययन नहीं किया है। उन्होंने कहा, ''केंद्रीय बजट से हमारे राज्य को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैं इसका अवलोकन कर रहा था। उन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर एक कार्यक्रम का नाम रखा है (गांधी के नाम पर रखे गये मनरेगा अधिनियम को निरस्त करने के बाद)।'' उन्होंने यहां पत्रकारों से बातचीत में अधिनियम को बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा, ''मुझे इस बजट में हमारे राज्य के लिए कोई बड़ा हिस्सा नजर नहीं आता।'' शिवकुमार ने कहा कि ''केंद्रीय बजट से बेंगलूरु को उम्मीदें थीं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे ''वैश्विक शहर'' कहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके लिए क्या किया है?'' उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चीनी कारखानों, विशेष रूप से सहकारी क्षेत्र के कारखानों को, उनकी सहायता के लिए कथित तौर पर कोई निर्णय या उपाय न किये जाने के कारण किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

सवारी डिब्बा कारखाना

निम्नलिखित ई-निविदा IREPS वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। फर्मों से अनुरोध है कि वे www.ireps.gov.in पर लॉगइन करें और निविदा के लिए अपना कोटेशन प्रस्तुत करें। इस निविदा के लिए मैन्युअल कोटेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

खुली निविदा संख्या	मदों का संक्षिप्त विवरण	निविदा मूल्य	निविदा बंद होने की तारीख और समय
2026476 212077	''एलएचबी डिवीजन और फ़र्निशिंग डिवीजन में उपलब्ध 15 ईओटी क्रेनों और 7 ट्रैवर्सर के रखरखाव के लिए दो वर्ष की अवधि हेतु वार्षिक रखरखाव अनुबंध'' हेतु कार्य अनुबंध।	₹ 5,06,36,857/-	11.02.2026 को 15.00 बजे तक

उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/संयंत्र

सवारी डिब्बा कारखाना

निम्नलिखित ई-निविदाएं IREPS वेबसाइट पर प्रकाशित की गई हैं। फर्मों से अनुरोध है कि वे www.ireps.gov.in पर लॉगइन करें और इन निविदाओं के लिए बोली लगाएँ। इस निविदा के लिए मैन्युअल कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

क्र. सं.	खुली निविदा सं.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	लगभग मूल्य (रुपये में)	निविदा बंद होने की तारीख और समय
1	2026377212107	पदाधिकारियों के लिए इंटीग्रल क्लब में सुधार।	1.09 करोड़	27.02.2026 @ 10.30 बजे
2	2026377212108	पेरम्बूर में सामुदायिक भवन का निर्माण	8.04 करोड़	27.02.2026 @ 10.30 बजे

सवारी डिब्बा कारखाना

निविदा सूचना संख्या 2025235212048 दि.: 23.01.2026

निम्नलिखित ई-निविदा IREPS वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। फर्मों से अनुरोध है कि वे www.ireps.gov.in पर लॉगइन करें और निविदा के लिए अपना कोटेशन प्रस्तुत करें। इस निविदा के लिए मैन्युअल कोटेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

क्र. सं.	खुली निविदा संख्या	मदों का संक्षिप्त विवरण	निविदा मूल्य (₹)	निविदा फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि/ खुलने की तिथि
1.	202523 5212048	सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नै में उपकरणों की हैंडलिंग और इंस्टलेशन सहित ईएमयू/एमईएमयू, ईएमयू (एसी)/एसडब्ल्यूएपी और कोलकाता मेट्रो कोच में वायरिंग का कार्य पूरा करना	₹ 25,74,39,998/-	16.02.2026 को 15.00 बजे तक

उप मुख्य बिजली इंजीनियर/फर-I

युवा व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर देश-प्रदेश के विकास में योगदान दें : भजनलाल शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को एक मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और युवाओं से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'फिट इंडिया मूवमेंट' में सक्रिय रूप से भाग लेने व स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की। शर्मा ने कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि सुबह जल्दी उठकर दौड़ने और व्यायाम से शरीर स्वस्थ व पूरे दिन शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे व्यायाम को अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाकर देश-प्रदेश के विकास में योगदान दें। शर्मा ने कहा, युवा राष्ट्र के भविष्य का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और विभिन्न क्षेत्रों में नए मानदंड स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उन विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं और भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में युवाओं के लिए खेल, रोजगार और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में व्यापक अवसर उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा, हमारे युवा केवल नौकरी तलाशने वाले ही नहीं रह गए बल्कि नौकरी देने वाले भी बन रहे हैं। शर्मा ने कहा कि सरकार युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने रामनिवास बाग से एयू जयपुर मैराथन को रवाना किया और बाद में प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मेहंदीपुर बालाजी महंत नरेशपुरी महाराज, अभिनेता मिलिंद सोमन और बड़ी संख्या में प्रतिभागी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने गत 2 वर्षों में युवाओं के लिए खेल, रोजगार, कौशल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अवसर उपलब्ध कराए हैं। इससे हमारा युवा रोजगार प्राप्त करने के साथ रोजगार प्रदाता भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं के हर सपने को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। कार्यक्रम में शर्मा ने मैराथन को हरी झण्डी दिखाकर रामनिवास बाग से रवाना किया।

उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को मेडल एवं प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन भी किया। इस अवसर पर मेहंदीपुर बालाजी महन्त नरेशपुरी महाराज, पं. सुरेश मिश्रा, अभिनेता मिलिंद सोमन, आर्किटेक्चर अनूप बरतरिया सहित अन्य अतिथिगण एवं बड़ी संख्या में प्रतिभागी मौजूद रहे।

'उड़ान योजना' बंद करना बेटियों के साथ अन्याय : डोटासरा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। कांग्रेस की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 'उड़ान योजना' बंद करने को लेकर राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि यह कदम प्रदेश की बेटियों के साथ अन्याय है। डोटासरा ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता और गरिमा को प्राथमिकता देते हुए 2021 में ऐतिहासिक निर्णय करते हुए राजस्थान में 'उड़ान योजना' शुरू की थी जिसके तहत प्रदेश की 1.45 करोड़ महिलाओं और छात्राओं को हर महीने 12 नि:शुल्क 'सेनेटरी नैपकिन' उपलब्ध कराए।

उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। कांग्रेस नेता ने कहा, लेकिन भाजपा सरकार ने पिछली सरकार की इस जनहितैषी योजना को बंद कर दिया।...ये जानकार पीड़ा होती है कि प्रदेश की बेटियां कपड़े और मौजे का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। उन्होंने दावा किया इससे बेटियों की पढ़ाई व सेहत पर असर पड़ रहा है और वे स्कूल छोड़ने को विवश हो रही हैं।

सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ से विधायक डोटासरा ने कहा, सीकर जिले के 39 सरकारी स्कूलों में आज भी बच्चियों के लिए अलग शौचालय तक नहीं हैं, पिछले तीन वर्षों में 19 हजार बच्चियां को सरकारी स्कूल छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को लेकर ऐतिहासिक और सख्त आदेश दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, अदालत ने स्पष्ट कहा है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए कि महिलाओं के लिए अलग और सुरक्षित शौचालय अनिवार्य रूप से हों, हर स्कूल में नि:शुल्क 'सेनेटरी पैड' उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने सवाल किया, जब कांग्रेस सरकार ने पहले ही उच्चतम न्यायालय की भावना के अनुरूप 'उड़ान योजना' शुरू कर दी थी, तो भाजपा सरकार ने उसे क्यों बंद किया? भाजपा ने बेटियों की सेहत, शिक्षा और गरिमा को सियासी हठधर्मिता की भेंट क्यों चढ़ाया?

मुख्यमंत्री से इस योजना को बहाल करने की मांग करते हुए डोटासरा ने कहा कि हर स्कूल में अलग शौचालय और नि:शुल्क सेनेटरी पैड उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए और उच्चतम न्यायालय के आदेशों का ईमानदारी से पालन किया जाए।

पर्यटन और संस्कृति के लिए 'बेमिसाल बूस्ट' बनेगा बजट : गजेंद्र सिंह शेखावत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/जोधपुर,। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे पर्यटन और संस्कृति क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया। बजट के बाद अपनी प्रतिक्रिया में शेखावत ने कहा कि यह बजट उम्मीदों से कहीं अधिक प्रोत्साहन देने वाला है। भारत को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार करता है। उन्होंने इस भविष्योन्मुखी विजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बजट में 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी' की स्थापना की घोषणा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि देश में फलते-फूलते पर्यटन क्षेत्र को देखते हुए प्रशिक्षित जनशक्ति की भारी मांग थी, जिसे यह संस्थान पूरा करेगा। देश के प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स को प्रशिक्षित करने की योजना न केवल पर्यटकों के अनुभव को सुधारेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए आजीविका के नए और सम्मानजनक अवसर भी पैदा करेगी।

बजट में 15 नए पुरातात्विक उत्खनन स्थलों को विकसित करने के प्रस्ताव पर खुशी जताते हुए शेखावत ने कहा कि यह कदम उन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, जिनकी रुचि इतिहास और शोध में है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी के जन्मस्थान वडनगर की सफलता के विस्तार के रूप में देखा। उन्होंने इकोलॉजिकल ट्रेल्स, माउंटेन ट्रेल्स और स्टारगेजिंग जैसे आधुनिक पर्यटन अनुभवों के लिए किए गए प्रावधानों को भी सराहा।

पूर्वोत्तर के लिए 'अष्टलक्ष्मी' विजन को दोहराते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वहां बौद्ध सर्किट और मठों के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ हिमालयी क्षेत्र में पांच विशेष पर्यटक ट्रेनों का संचालन कनेक्टिविटी को नया आयाम देगा।

उन्होंने बताया कि पांच नए मेडिकल हब्स की स्थापना 'मेडिकल वैल्यू टूरिज्म' के माध्यम से भारत को वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र बनाएगी। शेखावत ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि पिछले 10 वर्षों में आर्थिक उत्थान के कारण घरेलू पर्यटन में जबरदस्त उछाल आया है। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले एक साल में लगभग 294 करोड़ पर्यटकों ने देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए टीसीएस को 10 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने के फैसले को उन्होंने अंतरराष्ट्रीय टूर ऑपरेटरों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया।

भारत की सांस्कृतिक विरासत के विषय में शेखावत ने कहा कि हमें अपनी कहानियों को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें सही ढंग से पेश करने की जरूरत है। 'नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड' के माध्यम से एआई जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर भारत की अनूठी विरासत की मार्केटिंग पूरी दुनिया में प्रभावी ढंग से की जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि यह 'बेमिसाल बूस्ट' भारत को वैश्विक सांस्कृतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करेगा।

राजस्थान में बजट पर नेताओं की मिली-जुली प्रतिक्रिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान में राजनीतिक दलों के नेताओं ने केंद्रीय बजट पर अलग-अलग राय दी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे राज्य के लिए निराशाजनक बताया जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसे विकासोन्मुख एवं जन-केंद्रित करार दिया। भाजपा की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसे देश को आत्मनिर्भर, सशक्त और वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।

वसुंधरा राजे ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज करेगा और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा।

उन्होंने कहा कि बजट नागरिकों की आकांक्षाओं को पंख देगा। राजे ने इसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की दृष्टि का प्रतीक बताया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसके लिए बधाई दी। वहीं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि बजट में राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) का कोई उल्लेख नहीं है और न ही राज्य के लिए किसी नयी रेलवे या मेट्रो परियोजनाओं की घोषणा की गई।

गहलोत ने दावा किया कि बजट गरीबों, मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी आबादी को कोई बड़ी राहत देने में विफल रहा है। उन्होंने कहा, कथित डबल इंजन सरकार के बावजूद यह बजट राजस्थान के लिए पूरी तरह निराशाजनक साबित हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि इस बजट में लोक-लुभावनी घोषणाओं के स्थान पर राष्ट्र निर्माण की मूल भावना को महत्व दिया गया है।

केंद्रीय बजट संतुलित विकास का रोडमैप : शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय बजट 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह युवा, महिला, किसान, वंचित, गरीब और आम आदमी का बजट है। यह बजट तेज आर्थिक विकास, लोगों की आशाओं-आकांक्षाओं पर खरा उतरने और सबका साथ सबका विकास के तीन कर्तव्यों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि इस बजट ने राजस्थान को विकास की मुख्यधारा में और अधिक मजबूती से जोड़ने का काम किया है। इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सफर पूरा करेगा।

शर्मा ने कहा कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट बताता है कि पूरा देश 7 प्रतिशत की विकास दर के साथ पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म एक्सप्रेस पर शानदार परफॉर्म कर रहा है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति को समर्पित इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाले प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, महिलाओं के लिए शी मार्ट, हर जिले में एक बालिका छात्रावास जैसे प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी में छूट के साथ ही छोटे-बड़े उद्योगों, उत्पादकों, कारीगरों और कामगारों को वैश्विक बाजार में जाने के लिए नई दिशा दिखाई गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रदेश में सेमीकंडक्टर नीति और डेटा सेंटर नीति जारी की गई है। बजट में 40 हजार करोड़ रुपये से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के शुरू होने का फायदा राजस्थान को भी मिलेगा। इसी प्रकार डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज क्षेत्र को इंसेंटिव दिए गए हैं, उनसे भी राजस्थान लाभान्वित होगा। उन्होंने कहा कि मेगा टैक्सटाइल पार्क, 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और सोलर एवं माइनिंग क्षेत्र में की गई घोषणाओं से राज्य को विशेष रूप से फायदा मिलेगा। शर्मा ने कहा कि वी बी-जी राम जी योजना में नरेगा की तुलना में 86 हजार करोड़ से बढ़ाकर 95 हजार 692 करोड़ राशि का आवंटन किया गया है। राजस्थान को इससे अतिरिक्त राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि पशुपालन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है। बजट में दी गई लोन लिंक्ड केपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम का पशुपालकों को भरपूर लाभ मिलेगा।

अब घर बैठे एसएसओ आईडी और ई-मित्र से किए जा सकेंगे आवेदन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की एक जिला एक उत्पाद नीति-2024, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 और राजस्थान एमएसएमई नीति-2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। अब एसएसओ आईडी या ईमित्र के माध्यम से आवेदन किए जा सकेंगे। एक फरवरी से प्रारंभ हुई इस ऑनलाइन प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए जिला महाप्रबंध कों निर्देश दिए गए हैं कि इन नीतियों के तहत अब ऑफलाइन आवेदन नहीं लिए जाएंगे। साथ ही, इन नीतियों के तहत अब तक जारी किए स्वीकृति आदेशों को भी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त श्री सुरेश कुमार ओला ने बताया कि प्रक्रिया के ऑनलाइन होने से अब घर बैठे ही आवेदन किए जा सकेंगे। साथ ही, आवेदन की स्थिति की रियल टाइम जानकारी भी मिल सकेगी और बार-बार कार्यालय भी नहीं आना पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा निवेश प्रक्रिया के सरलीकरण और डिजिटलाइजेशन की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के कारण ही व्यापार और उद्योग स्थापना की प्रक्रिया के सरलीकरण के मामले में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

राज्य के विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 के तहत सभी 41 जिलों में एक-एक उत्पाद की पहचान की गई है। इसके तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 20 लाख रुपये तक की मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। साथ ही, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपये तक अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर पर 3 लाख रुपये तक पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा देय है। विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपये तक सहायता, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष का 2 साल तक पुनर्भरण और कैटलॉगिंग और ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 75 हजार रुपये तक एकमुश्त सहायता का प्रावधान है।

राज्य के उद्यमियों को निर्यातक बनाने के उद्देश्य से लागू की राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति- 2024 के तहत निर्यातकों के दस्तावेजीकरण पर 5 लाख रुपये और तकनीकी अपग्रेडेशन पर 50 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 2 लाख रुपये तक का पुनर्भरण किया जाता है।

राज्य के छोटे उद्यमियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से लागू की राजस्थान एमएसएमई नीति-2024 के तहत ऋण पर अतिरिक्त 2 फीसदी ब्याज अनुदान दिया जाता है। साथ ही, एसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपये तक की सहायता, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी तथा सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपये तक का अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर पर 3 लाख रुपये तक का पुनर्भरण का प्रावधान है। विपणन के लिए आयोजनों में भाग लेने पर 1.5 लाख रुपये तक का अनुदान, डिजिजल उपकरणों पर 50 हजार रुपये तक पुनर्भरण, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 50 हजार रुपये तक का पुनर्भरण किया जाता है।

ऊंची दुकान, फीका पकवान : बजट में राजस्थान की अनदेखी पर बरसे अशोक गहलोत

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने केंद्रीय बजट को प्रदेश की जनता के साथ छलावा करार दिया है। बजट पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा कि देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का बजट भाषण में नाम तक न होना यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार का राज्य के प्रति रवैया 'सौतेला' है। एठउझ और रेलवे को लेकर जताई नाराजगी गहलोत ने विशेष रूप से ईआरसीपी (एठउझ) का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 13 जिलों की इस महत्वपूर्ण जल परियोजना को लेकर बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने बजट की खामियों को गिनाते हुए निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर केंद्र को घेरा। गरीब, मजदूर और श्रमिकों के लिए किसी बड़ी राहत योजना का अभाव। राजस्थान जैसे भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य के लिए किसी विशेष वित्तीय पैकेज की कमी।

कड़ाके की ठंड से मिली राहत

जयपुर। राजस्थान के लोगों को रविवार को कड़ाके की ठंड से राहत मिली और राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग के अनुसार, अलवर में 7.2 डिग्री सेल्सियस, लूणकरनसर में 7.7 डिग्री सेल्सियस, पाली में 8.3 डिग्री सेल्सियस, जवाई बांध (पाली जिला) में 9.6 डिग्री, श्रीगंगानगर में 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बचाया कि अजमेर में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों में 1.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और अगले 24 घंटों तक मौसम की स्थिति इसी प्रकार बनी रहने का अनुमान है।

ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से तीन लोगों की मौत

जयपुर। जयपुर स्थित एक कारखाने में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की घटना में मरने वालों की संख्या तीन हो गई है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह हादसा शनिवार रात विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के करणी विहार कॉलोनी स्थित कारखाने में उस समय हुआ, जब सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी जा रही थी तभी एक सिलेंडर में विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि कारखाने पर लगी टिन शेड उड़ गई और एक दीवार भी ढह गई। पुलिस ने बताया कि एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी पहचान झारखंड निवासी मुन्ना राय के रूप में हुई है। विश्वकर्मा थाना प्रभारी रविन्द्र सिंह नरूका ने बताया कि हादसे में मुरलीपुरा निवासी कारखाना प्रबंधक विनोद गुप्ता (45) और झारखंड निवासी कर्मचारी शिबू उर्फ अनुवा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि विनोद को मणिपाल अस्पताल और शिबू को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर रात उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई आरोप है कि भट्ट परिवार ने अलग-अलग नामों से फर्जी बिल तैयार किए और शिकायतकर्ता से पैसे अंतरित करवाए। फिल्म निर्माण के लिए निर्धारित यह पैसा कथित तौर पर उन्होंने अपने खातों में जमा कर लिया और उसका इस्तेमाल किया। नवंबर 2025 में मामला दर्ज किया गया तथा राजस्थान पुलिस सात दिसंबर को इस दंपति को, उदयपुर निवासी दिनेश कटारिया और भट्ट के मैनेजर महबूब अंसारी को मुंबई से गिरफ्तार कर उदयपुर ले आई। शिकायतकर्ता उदयपुर निवासी है।। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

न्यायालय ने फिल्मकार विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को जमानत नहीं दी

जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी के एक मामले में जेल में बंद फिल्मकार विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी और दो अन्य लोगों की जमानत याचिकाएं शनिवार को खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी ने कहा कि इस स्तर पर आरोपियों को जमानत देना उचित नहीं होगा। सुनवाई के दौरान, विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) ने यह तर्क देते हुए जमानत याचिकाओं का विरोध किया कि मामले की जांच अभी जारी है तथा आरोपियों से और पूछताछ की जरूरत है।

हरियाणा में आयोजित सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में राजस्थान पहली बार हुआ शामिल

जयपुर। राजस्थान पहली बार हरियाणा में आयोजित होने वाले सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में सहभागी बना है। 31 जनवरी को आरंभ हुए इस मेले में राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसिको) द्वारा बनाया गया 'राजस्थान चौक' देश-विदेश के प्रतिभागियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहां राजस्थान की कला और संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्प उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पंच गौरव जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। इस कड़ी में ही इस अंतरराष्ट्रीय मेले में प्रदेश की कला-संस्कृति और उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है।

राजसिको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शिखर अग्रवाल ने बताया कि 15 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस मेले में राजस्थान के हस्तशिल्प और ओडीओपी उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए 20 स्टॉल्स लगाई गई हैं। इन पर महिला एवं बाल विकास विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थली के विशिष्ट हस्तशिल्प एवं अन्य पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। अग्रवाल ने बताया कि मेले में राज्य की समृद्ध लोककला, हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पाद एवं सांस्कृतिक विरासत को देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए 'राजस्थान चौक' बनाया गया है। यहां प्रदर्शित उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनेगी।

'यह बजट प्रधानमंत्री मोदी में लोगों के अटूट भरोसे को दर्शाता है'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को कहा कि रविवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक अगला कदम है, साथ ही गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं समेत समाज के हर वर्ग की भलाई सुनिश्चित करता है।

नवीन ने कहा, ''यह बजट पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर लोगों के अटूट भरोसे को दिखाता है। प्रधानमंत्री का 'सबका साथ, सबका विकास' का सिद्धांत इस बजट के हर पहलू में साफ दिखता है।'' उन्होंने कहा कि 2026-27 का बजट भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार की नीतियों और सुशासन की निरंतरता को साफ तौर पर दिखाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में नौवीं बार बजट पेश किया।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ''यह बजट 2047 तक विकसित भारत के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे है, साथ ही गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं समेत समाज के हर वर्ग की भलाई सुनिश्चित करता है।'' उन्होंने कहा, ''मैं पूरे दिल से बजट का स्वागत करता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवीं बार देश का बजट पेश किया है, यह भारत सरकार की नीति और सुशासन की निरंतरता को साफ दिखाता है।'' नवीन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था लगभग सात प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, उससे संकेत मिलता है कि देश के जीएसपी और जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) लगातार मजबूत हो रहे हैं, जबकि

महंगाई को नियंत्रण में रखा गया है। उन्होंने कहा, ''यह एक सोच-समझकर बनाया गया बजट है, जो सबको साथ लेकर चलने वाली तरक्की में भरोसा दिखाता है और यह साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार का शिक्षा और अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाओं को मजबूत करने का इरादा है।'' भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह ''युवा केंद्रित बजट'' भी है क्योंकि यह उनके लिए रोजगार के नए मौके पैदा करेगा। उन्होंने कहा, ''सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए और बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए के जरिए बनाई गई मजबूत समर्थन प्रणाली साफ तौर पर दिखाती है कि सरकार रोजगार के नए मौके पैदा करने पर कितना गंभीर है।'' भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बजट में महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' के दृष्टिकोण को भी साफ तौर पर दिखाया गया है। उन्होंने कहा, ''इससे हमारे कारीगरों और छोटे कुटीर उद्योगों को फ़ायदा होगा तथा ग्रामीण इलाकों में रोजगार मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्रों के विकास में भी सरकार के लगातार प्रयास साफ दिखते हैं।''

भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ''मैं परिवहन क्षेत्र के लिए बजट में राशि बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी बधाई देता हूं। इसी तरह, रक्षा के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान साफ दिखाता है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।''

नवीन ने कहा कि बजट समाज के हर तबके को विकास और तरक्की में शामिल करने के ''साफ इरादे'' को दिखाता है। उन्होंने कहा कि चाहे युवा हों, महिलाएं हों, मध्यम वर्ग के लोग हों या समाज का कोई और तबका, बजट में सभी के लिए साफ दिशा है और संसाधन दिए गए हैं।

माघी पूर्णिमा पर 2.10 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई

प्रयागराज/भाषा। प्रयागराज में आयोजित किए जा रहे माघ मेले में रविवार को माघी पूर्णिमा स्नान पर्व पर 2.10 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम और गंगा में डुबकी लगाई। मेला प्राधिकरण के एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कड़ाके की ठंड और कोहरे के बावजूद कल रात 12 बजे से ही श्रद्धालुओं का मेला क्षेत्र में आगमन और गंगा स्नान जारी रहा। आज शाम छह बजे तक 2.10 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में स्नान किया। जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि पिछले एक महीने से मेले में कल्पवास कर रहे कल्पवासियों का रविवार को अंतिम गंगा स्नान है, इसलिए उनके परिजन उन्हें घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। उन्होंने बताया, सुबह घना कोहरा होने के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए और सभी घाटों पर स्नान सुचारू ढंग से चला।'सभी घाटों पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम तैनात हैं। इसके अलावा नाविकों और गोताखोरों को भी सभी घाटों पर तैनात किया गया है।''

जब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, 'मियां' समुदाय को परेशानी का सामना करना पड़ेगा : हिमंत

गोलपाड़ा/भाषा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार को कहा कि जब तक वह सत्ता में रहेंगे, 'मियां' समुदाय को ''मुसीबतों'' का सामना करना पड़ेगा। हिमंत ने कहा कि उन्हें (मियां समुदाय के लोगों को) लगातार समस्याओं का सामना करना चाहिए, ताकि वे राज्य छोड़कर चले जाएं। उन्होंने कहा कि चूंकि मियां 'अवैध बांग्लादेशी' हैं, इसलिए उन्हें राज्य में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हिमंत ने यहां एक सरकारी कार्यक्रम के इतर संवाददाताओं से कहा, ''अगर मैं असम में रहा, तो उन्हें (मियां समुदाय के लोगों को) परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वे यहां शांति से नहीं रह सकते। अगर हम उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, तभी वे यहां से जाएंगे।'' 'मियां' मूल रूप से असम में बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अपमानजनक शब्द है। गैर-बांग्ला भाषी लोग इन लोगों को आमतौर पर बांग्लादेशी प्रवासी के रूप में पहचानते हैं।

बंगाल में आगामी चुनाव में हार की आशंका से भाजपा एसआईआर का कर रही दुरुपयोग : ममता

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में अपनी हार को लेकर आश्वस्त है, इसलिए वह विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख ने नई दिल्ली रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, '' उन्हें (भाजपा को) पता है कि वे बंगाल में हार जाएंगे। इसीलिए वे एसआईआर का इस्तेमाल कर रहे हैं।''

बनर्जी की सोमवार शाम को मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात निर्धारित है। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा, ''अगर उनमें हिम्मत है, तो मैं उनसे अपील करूंगी कि वे निर्वाचन आयोग और अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग करने के बजाय राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ें।'' बनर्जी ने दावा किया कि इसी तरह की प्रथाओं ने अन्य राज्यों में चुनावी परिणामों को प्रभावित किया है। भाजपा को चुनौती देते हुए बनर्जी ने कहा, '' मैं उनसे (भाजपा से) कहूंगी कि अगर हिम्मत है तो राजनीतिक लड़ाई लड़ो। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। एक-एक इंच की लड़ाई।'' विपक्षी दलों की संभावनाओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, '' लेकिन बंगाल (बंगाल की जनता) जीतेगा। तमिलनाडु जीतेगा। केरल जीतेगा। और असम में वे (भाजपा) हारेंगे।''

बजट में बंगाल का जिक्र नहीं, सरकार हमें 'बांग्लादेशी' के रूप में देखती है : अभिषेक

नई दिल्ली/भाषा। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल के लोगों को ''बांग्लादेशी'' के रूप में देखने का आरोप लगाया और बजट भाषण में राज्य का उल्लेख न करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की कड़ी आलोचना की।

बजट के बारे में पूछे जाने पर बनर्जी ने इसे ''अनाम, आधारहीन और अदूरदर्शी'' करार देते हुए कहा कि इसमें किसी भी समुदाय के लिए कोई समाधान नहीं है। उन्होंने कहा, ''बजट भाषण 85 मिनट लंबा था- 5,100 सेकंड का... बंगाल का ज़िक्र तक नहीं हुआ। बंगाल की बात छोड़िए; किसान, युवा...किसी के लिए भी कुछ ठोस नहीं था।'' बनर्जी ने कहा, ''वे एआई, स्किल इंडिया, तकनीकी प्रगति की बात करते हैं; युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, रोजगार कैसे पैदा होगा, इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है। किसानों की आय बढ़ाने के बारे में कुछ नहीं है, किसी भी समुदाय के लिए कुछ नहीं है।'' उन्होंने कहा, ''यह केंद्र सरकार और उसके मंत्री हैं, जिन्होंने बजट पेश किया, वही हमें बांग्लादेशी कहते हैं। बजट में बंगाल का तो ज़िक्र तक नहीं किया गया। जल जीवन मिशन का पैसा रोक दिया गया है, उन्होंने पुराने वादे भी पूरे नहीं किए हैं।''

केंद्रीय बजट 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने का आधार तैयार करेगा : सम्राट चौधरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के विज़न को साकार करने की दिशा में मजबूत आधार तैयार करेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे पहले दिन में संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। यह उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया लगातार नौवां बजट है। चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, केंद्रीय बजट 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत के तहत भारत की समृद्धि की यात्रा में जनभागीदारी को सुदृढ़ करेगा। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि वाराणसी और सिलीगुड़ी के बीच उच्च-गति रेल कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है, जो बिहार से होकर गुजरेगा और इससे राज्य को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि वाराणसी-पटना अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास और उसके साथ रखरखाव फैक्टरी की स्थापना के प्रस्ताव से भी बिहार को सीधा लाभ मिलेगा, जिसके लिए भूमि पहले ही उपलब्ध करा दी गई है।

चौधरी ने कहा, इसके अलावा, सभी जिला मुख्यालय अस्पतालों में मेडिकल ट्रॉमा सेंटर और आईसीयू बनाए जाएंगे, तथा तीन नए आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इधर, पूर्व मंत्री एवं झंझारपुर से विधायक नीतीश मिश्रा ने केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला दूरदर्शी रोडमैप बताया।

डीआरडीओ के लिए बजट कभी बाधा नहीं रहा : संयुक्त निदेशक

कोलकाता/भाषा। डीआरडीओ के संयुक्त निदेशक बिनॉय कुमार दास ने रविवार को कहा कि अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों और हथियार प्रणालियों के डिजाइन और विकास में लगे प्रमुख सरकारी अनुसंधान संगठन के लिए बजट कभी भी बाधा नहीं रहा है।

दास ने कहा कि रक्षा अनुसंधान और उत्पादन क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हमेशा से भरपूर सहयोग मिलता रहा है। उन्होंने कहा, ''सरकार ने हमेशा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को बिना शर्त सहयोग दिया है और बजट हमारे लिए कभी बाधा नहीं रहा है।''

'एप्सटीन फाइल' के मामले पर स्पष्टीकरण दें प्रधानमंत्री : कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने अमेरिका में जारी एप्सटीन फाइल में हुए खुलासों के बाद रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।

कांग्रेस के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने 'एक्स' पोस्ट किया, एप्सटीन फाइल के नए बैच की रिपोर्ट इस बात की बड़ी चेतावनी हैं कि किस तरह के लोगों की प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच है और वह विदेशी दबाव/हेरफेर के प्रति कितने संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस मांग करती है कि प्रधानमंत्री स्वयं इन खुलासों पर सामने आकर सच बताएं, जो गंभीर सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस नेता

ने सवाल किया, क्या उन्होंने जेफ्री एप्सटीन से मुलाकात की? या उन्होंने किसी को उससे मिलने भेजा? एप्सटीन के साथ उनकी बातचीत में क्या-क्या शामिल था?

वेणुगोपाल ने दावा किया कि उतनी ही चिंताजनक एक रिपोर्ट यह भी है कि जब भारत की विदेश नीति में बड़ा बदलाव हो रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी एप्सटीन जैसे दागी लोगों की धुन पर नाच-गा रहे थे। उनका कहना है, भारत के लोगों को जवाब चाहिए।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री को स्वयं स्पष्टीकरण देना चाहिए।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी सवाल किया कि क्या 2019 के लोकसभा चुनाव के आसपास प्रधानमंत्री मोदी एप्सटीन संपर्क में थे। भाजपा ने शनिवार को कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भ्रामक सूचना फैलाने का आरोप लगाया था और कहा था कि कांग्रेस ने जेफ्री एप्सटीन से जुड़ी जांच फाइलों के एक सामान्य ईमेल अंश को तोड़-मरोड़कर राजनीतिक रूप से बदनाम करने की कोशिश की है।

विदेश मंत्रालय ने जेफरी एपस्टीन से संबंधित जांच फाइलों में प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ को शनिवार को सिरे से खारिज करते हुए इसे ''एक दोषी अपराधी के तुच्छ चिंतन से अधिक कुछ नहीं'' करार दिया।

ओडिशा को बजट में केवल खनिज निकालने के लिए धन मिलता है, जन कल्याण के लिए नहीं : पटनायक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

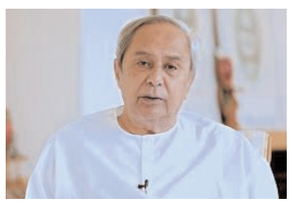

भुवनेश्वर/भाषा। बीजू जनता दल (बीजद) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने रविवार को केंद्रीय बजट में ओडिशा के लिए किए गए प्रावधानों पर निराशा प्रकट करते हुए कहा कि राज्य को केवल उसके प्राकृतिक संसाधनों के खनन के लिए आवंटन मिलता है और जन कल्याण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

पटनायक ने संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओडिशा और उसके लोगों को बजट में जो मिला है, वो उससे ज्यादा तथा बेहतर के हकदार हैं। उन्होंने कहा, ''जैसा कि पूरे केंद्रीय बजट से पता चलता है, ओडिशा को सिर्फ उसके प्राकृतिक संसाधन लेने के लिए आवंटन मिल रहा है और जब राज्य के लोगों के फायदे के लिए संसाधनों के आवंटन की बात आती है, तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता है।''

पटनायक ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ''मैं केंद्र सरकार द्वारा आज पेश किए गए बजट 2026 पर अपनी निराशा व्यक्त करता हूं। बजट ने ओडिशा और उसके लोगों को कोई खास लाभ नहीं दिया है।'' उन्होंने कहा कि ओडिशा के लोगों को उम्मीद थी कि डबल इंजन वाली सरकार अवसंरचना, रोजगार सृजन और राज्य को मिलने वाले अतिरिक्त आवंटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास को रफ्तार देगी, लेकिन ''राज्य को बहुत कम मिला है''। हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री ने बजट में ओडिशा में 'दुर्लभ खनिज गलियारे' की स्थापना के प्रस्ताव का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज्य कई आवश्यक खनिजों का अग्रणी उत्पादक है और अपने समृद्ध संसाधनों के जरिए हमेशा राष्ट्र निर्माण में मदद करेगा। पटनायक ने कहा कि बजट में फिर से खनिज समृद्ध क्षेत्रों और औद्योगिक केंद्रों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा की गई, लेकिन यह प्रस्ताव एक दशक पुराना है और ''जमीन पर कोई प्रगति नहीं हुई है''। पटनायक ने यह भी कहा कि यह बहुत निराशा की बात है कि शहरों के बीच 'ग्रोथ कनेक्टर' के तौर पर सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा में ओडिशा का नाम नहीं है।

बजट गरीब और मध्यम वर्ग विरोधी, आंकड़े विश्वसनीय नहीं : अमित मित्रा

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रधान मुख्य सलाहकार अमित मित्रा ने रविवार को केंद्रीय बजट को ''गरीब-विरोधी, किसान-विरोधी और मध्यम वर्ग-विरोधी'' बताया तथा वित्त वर्ष 2015-16 की तुलना में सामाजिक क्षेत्र के आवंटन में की गई भारी कटौती की आलोचना की। मित्रा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि किसानों, युवाओं और कमजोर वर्गों को प्रभावित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में वर्षों से लगातार कटौती की गई है जबकि घोषित आवंटन वास्तविक व्यय में तब्दील नहीं हो पाए हैं। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि कुल व्यय का 5 से 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होना चाहिए था, लेकिन असल में यह वित्त वर्ष 2015-16 के 3.8 प्रतिशत से घटकर वर्तमान बजट अनुमान में 2.60 प्रतिशत रह गया है। उर्वरक सब्सिडी के मुद्दे पर मित्रा ने आरोप लगाया कि 2015-16 में कुल व्यय के 4.04 प्रतिशत से आवंटन घटकर मौजूदा बजट अनुमानों में 3.19 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा, ''यह एक गंभीर कटौती है और किसान विरोधी कदम है।'' उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यकों - के लिए आवंटन में कमी का भी मुद्दा उठाया और कहा कि व्यय 2015-16 में कुल बजट के 0.21 प्रतिशत से घटकर 0.19 प्रतिशत हो गया है और अनुमान है कि इसमें और भी गिरावट आएगी।

एनडीडीबी लैब की रिपोर्ट में तिरुपति के लड्डुओं में पशु वसा होने की 'पुष्टि' हुई थी : नायडू

कुप्पम (आंध्र प्रदेश)/भाषा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को कहा कि उन्होंने वाईएसआरसीपी के शासनकाल में टीटीडी को आपूर्ति किए गए घी में पशु वसा मिली होने की बात एनडीडीबी की प्रयोगशाला की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद ही कही थी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में घी में मिलावट होने की पुष्टि की गई थी।

नायडू ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को कथित तौर पर विवादों में घसीटने के लिए विपक्षी दल वाईएसआरसीपी पर निशाना साधा। उन्होंने मौजूदा कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार सिंघल के स्थानांतरण से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा, तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी श्यामला राव ने एनडीडीबी से घी के नमूनों की रिपोर्ट मंगवाई थी। रिपोर्ट मिलने के बाद, मैंने कहा कि इन नमूनों में पशु वसा है, यानी कि इसमें मिलावट हुई है। मेरे यह कहने के बाद, वाईएसआरसीपी ने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रशासक के रूप में उन्होंने घी में मिलावट के मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी उनके चरित्रहनन में जुटी है और उनसे माफी की मांग कर रही है।

राकांपा के विलय से पहले मुझे इस बारे में अवश्य सूचित करते अजित पवार : फडणवीस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विलय की चर्चाएं अंतिम चरण में होतीं, तो दिवंगत अजित पवार ने उन्हें इसके बारे में जरूर बताया होता। फडणवीस ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार सभी तरह की जानकारी उनके साथ साझा करते थे।

राकांपा (शप) के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि उनके भतीजे एवं राकांपा नेता अजित पवार ने दोनों गुटों के बीच 'विलय' की घोषणा के लिए 12 फरवरी की तारीख तय कर ली थी, लेकिन अब उनकी (अजित पवार) मौत के कारण विलय की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। अजित पवार और शरद पवार के बीच 17 जनवरी को हुई बैठक का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फडणवीस ने हालांकि रविवार को कहा कि उन्हें अजित पवार की चाचा शरद पवार के साथ हुई बातचीत की जानकारी नहीं है और उन्हें 12 फरवरी की तारीख के बारे में भी नहीं पता। मुख्यमंत्री ने कहा, ''क्या राकांपा के विलय की बातचीत हमारी जानकारी के बिना अंतिम रूप ले सकती है? हमें 12 फरवरी की उस तारीख की जानकारी नहीं है जिसे विलय की औपचारिक घोषणा की तारीख बताया जा रहा है।'' फडणवीस ने कहा कि राकांपा एक स्वतंत्र पार्टी है जो अपने फैसले खुद लेती है, लेकिन भाजपा की सहयोगी होने के नाते, उससे आगे बढ़ने से पहले भाजपा से परामर्श करने की उम्मीद की जाती है। भाजपा द्वारा राकांपा के दोनों गुटों के विलय का विरोध किए जाने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा कि उनकी पार्टी ने किसी का विरोध नहीं किया है। फडणवीस ने कहा, ''अगर पवार विलय पर काम कर रहे थे, तो क्या वह भाजपा को विश्वास में लिए बिना ऐसा करते?

कोहली ने मुझे दिल्ली के लिए 200 प्रतिशत देने के लिए प्रेरित किया : दोसेजा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। रणजी ट्रॉफी के ग्रुप चरण का समापन सर्वाधिक व्यक्तिगत रन बनाने वाले बल्लेबाज के तौर पर करने वाले दिल्ली के आयुष दोसेजा भारतीय सुपरस्टार विराट कोहली के अनुशासन और फिटनेस 'रूटीन' को अपनाने का लक्ष्य रख रहे हैं। इस 23 साल के बल्लेबाज ने इस सत्र की शुरुआत में हैदराबाद के खिलाफ पदार्पण किया था।

उन्होंने मौजूदा रणजी सत्र को चार शतक और पांच अर्धशतक की मदद से 949 रन के साथ खत्म किया। इस दौरान उनका औसत 105.44 का रहा। अपने पदार्पण सत्र में ही कप्तानी का दायित्व मिलने के बाद दोसेजा ने मुंबई के खिलाफ दूसरी पारी में नाबाद 159 रन बनाकर मैच ड्रॉ करने में अहम भूमिका निभाई। मौजूदा सत्र में उनके शानदार प्रयास के बावजूद दिल्ली आठ टीमों की ग्रुप तालिका में छह ड्रॉ और एक हार से सातवें पायदान पर रही। दोसेजा ने मैच के बाद कहा, ''कोहली ने मुझसे कहा था, 'जब भी आप मैदान पर जाएं, तो 200 प्रतिशत दें क्योंकि आप दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यह बहुत बड़ी बात है '। अगर मुझे भारत के लिए खेलना है, तो मुझे इसी मानसिकता के साथ खेलना होगा। इस युवा बल्लेबाज ने बताया, '' कोहली ने कहा था कि मैदान पर जाने के बाद खुद के विकेट बचाने के लिए खेलने की जगह मुझे मैच पर अपना प्रभाव कायम करना होगा। मैं उनके इस संदेश और फिटनेस की 'रूटीन' को अपनाने की कोशिश करता हूं। मैं खुद को मैच के लिए जितना संभव हो उतना फिट रखने की कोशिश करता हूं।'' नियमित कप्तान आयुष बडोनी के भारत ए टीम से जुड़ने के कारण दोसेजा को अपने पहले सत्र में ही टीम की कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया।

निशाना — दक्षिण भारत राष्ट्रमत

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (मध्य) असम में आयोजित आदिवासी सम्मेलन के दौरान पारंपरिक धनुष-बाण थामे हुए।

सुविचार

कुछ लोग सपने देखते रहते हैं और कुछ लोग जल्दी उठकर उन सपनों को सच कर देते हैं।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देगा यह बजट

केंद्र सरकार ने अपने बजट में संतुलन रखते हुए सभी वर्गों का ध्यान रखने की कोशिश की है। इससे अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। सरकार ने बायोफार्मा क्षेत्र के लिए जो घोषणाएं की हैं, वे देश को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद करेंगी। समर्पित दुर्लभ धातु गलियारों की स्थापना के लिए ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को मदद देने के प्रस्ताव से खनन, प्रसंस्करण और अनुसंधान के नए द्वार खुलेंगे। देश में रसायन उत्पादन बढ़ाने के लिए तीन समर्पित केमिकल पार्क स्थापित करने की योजना से विदेशों पर निर्भरता कम होगी। तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने से देशवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। सरकार ने 20 हजार से ज्यादा पशु चिकित्सकों की उपलब्धता की घोषणा कर पशुधन स्वास्थ्य एवं संवर्द्धन का ध्यान रखा है। निजी क्षेत्र में पशु रोग विशेषज्ञ और पैरा पशु शल्य महाविद्यालय एवं अस्पतालों की स्थापना के लिए ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी सहायता गांवों में पशुपालकों के लिए मददगार साबित होगी। 15 हजार माध्यमिक विद्यालयों और पांच सौ महाविद्यालयों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में मदद का प्रस्ताव नई प्रतिभाओं को आकार देगा। वीजीएफ / पूंजीगत सहायता के जरिए हर जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना करने से नारी शक्ति को संबल मिलेगा। इससे पढ़ाई और रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी। आईआईएम के सहयोग से हाइब्रिड मोड में 12 हफ्ते के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से 10 हजार गाइडों के कौशल उन्नयन के लिए योजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, युवाओं को रोजगार में मदद मिलेगी।

पांच सौ जलाशयों और अमृत सरोवरों के विकास, पशुपालन और उच्च मूल्य वाली कृषि को प्रोत्साहन देने से किसानों को फायदा होगा। उन्हें परंपरागत खाद्यान्न की जगह नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसी फसलों से जोड़ने से खेती मुनाफे का सौदा बनेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और खुबानी की खेती को प्रोत्साहन मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इसके अलावा, देश में पोषण की स्थिति में सुधार होगा। बहु-भाषी एआई टूल 'भारत-विस्तार' किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। खेती संबंधी जानकारी आसानी से उपलब्ध होने से किसानों के लिए जोखिम कम होगा। वे सही समय पर सही फैसले लेकर फसलों से ज्यादा फायदा ले सकेंगे। 17 औषधियों पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट देने से कई परिवारों को राहत मिलेगी। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना, वस्त्र क्षेत्र में नई योजनाओं और उच्च तकनीकी उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलने से भारत के उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम होंगे। 10,000 करोड़ रुपए की समर्पित एसएमई निधि से उत्कृष्ट उद्यमों का निर्माण होगा। देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित योजना रोजगार के अनेक अवसरों का सृजन करने के साथ विदेशी मुद्रा भंडार के लिए महत्त्वपूर्ण साबित होगी। पड़ोसी देशों के अलावा यूरोप से भी हजारों लोग भारत में इलाज कराने आते हैं। विभिन्न शहरों के बीच सात उच्च-गति रेल कॉरिडोर विकसित करने के फैसले से करोड़ों नागरिक लाभान्वित होंगे। ये कॉरिडोर विकास संयोजक की भूमिका निभाएंगे। इनसे आवागमन तेज होगा। आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। भारत के विकास में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। आज ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ने, नई तकनीक अपनाने और ऋण उपलब्धता सुलभ कराने की जरूरत है। सरकार ने 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग' पर उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखकर समावेश और उपभोक्ता सुरक्षा पर जोर दिया है। अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इन घोषणाओं को धरातल पर शीघ्र लागू कर विकसित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करे।

ट्वीटर टॉक

विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करने वाला केंद्रीय बजट 2026-27 देश के उज्ज्वल भविष्य की स्पष्ट झलक प्रस्तुत करता है। आज इस जनकल्याणकारी बजट को लाइव देखने का अवसर मिला, जिसमें भारत के समग्र विकास की दूरदृष्टि साफ दिखाई देती है।

-दिया कुमारी

माघ पूर्णिमा के दिव्य पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि का निरंतर संचार हो। यह शुभ तिथि प्रत्येक हृदय में श्रद्धा, सद्भाव और सकारात्मक चेतना का प्रकाश प्रसारित करे।

-वसुंधरा राजे

मानवता और करुणा का अमर संदेश देने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। उनकी शिक्षाएं तथा विचार सम्पूर्ण मानव समाज के कल्याण, समानता और न्याय की सीख देते हैं जिनका हमें अपने जीवन में अनुकरण करना चाहिए।

-अशोक गहलोत

प्रेरक प्रसंग

प्रकृति की प्रबलता

धर्मयात्रा पर चलते-चलते महात्मा बुद्ध ने जब थकान महसूस की, तो सुस्ताने के लिए एक वृक्ष के नीचे छाया में विश्राम करने लगे। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनन्द से कहा, 'प्यास लगी है तुम निकट के झरने से पानी ले आओ।' आनन्द जब झरने के तल पर पानी लेने गया तो कुछ देर पहले एक बैलगाड़ी के गुजरने से पानी गंदला हो गया। फिर आनन्द स्वच्छ जल की तलाश में अन्यत्र जाने लगा। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, 'आनन्द धीरज रखो, इसी झरने से पानी ले आना।' फिर कुछ समय बाद आनन्द उसी झरने पर पानी लेने गया तो उसने देखा कि गंदला पानी बह चुका था। उसने प्रसन्न होकर कमंडल में जल भरा और ले आया। महात्मा बुद्ध ने तब मुस्कराते हुए आनन्द से कहा, 'तुम जीवन में प्रकृति को देखा करो, परिस्थिति को नहीं। हमेशा परिस्थिति बदल जाती है लेकिन प्रकृति सदैव स्थिर रहती है। यदि मनुष्य में सुसंस्कार, श्रेष्ठता आदि सद्गुणों का समावेश है तो तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद वे दीर्घकाल में महकते हैं। प्रकृति निर्विवाद रूप से प्रबल है। वह श्रेष्ठता को स्वतः स्थापित कर देगी।'

सामयिक

इस पूरे बजट की सबसे बड़ी कमी किसानों को लेकर किसी ठोस और नई घोषणा का न होना है। कृषि क्षेत्र अभी भी महंगाई, लागत और आय की अनिश्चितता से जूझ रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना समग्र विकास अधूरा रहेगा, यह सच्चाई इस बजट में अपेक्षाकृत कम झलकती है। कुल मिलाकर, बजट 2026-27 संतुलित प्रयास माना जा सकता है। यह न तो लोकलुभावन है और न ही कठोर सुधारवादी। सरकार ने भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए दिशा स्पष्ट की है लेकिन महंगाई, रोजमर्रा का खर्च और आय की सुरक्षा जैसी आम आदमी की तात्कालिक चिंताओं पर सीधी राहत सीमित है।

बजट 2026-27 : लोकलुभावन वादों से दूर

योगेश कुमार गोयल

मोबाइल : 9416740584.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 को एक ओर जहां सरकार के घटक दलों द्वारा विकसित भारत का बजट और बदलते भारत की राजनीतिक-आर्थिक प्राथमिकताओं तथा सरकार की दीर्घकालिक सोच का आईना बताया गया है, वहीं विपक्ष द्वारा इसे पूरी तरह दिशाहीन बजट करार दिया गया है। वैसे निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवीं बार बजट पेश कर संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। सवाल यह नहीं है कि बजट कितना बड़ा है या कितने नए आंकड़े पेश किए गए हैं बल्कि यह है कि क्या यह बजट महंगाई से जूझ रहे आम नागरिक के वर्तमान को कुछ राहत देता है और भविष्य के लिए भरोसेमंद आधार तैयार करता है? बजट के तमाम महत्वपूर्ण प्रावधानों का आकलन किया जाए तो यह बजट विकास, निवेश, बुनियादी ढ़ांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत की स्पष्ट झलक तो दिखाता है लेकिन इसके साथ ही इसमें कई ऐसे खाली स्थान भी हैं, जो आम आदमी और विशेषकर किसान, निम्न आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए निराशा पैदा करते हैं। सरकार ने इस बार तात्कालिक लोकलुभावन उपायों से दूरी बनाते हुए दीर्घकालिक क्षमता निर्माण पर जोर दिया है। यह दृष्टिकोण आर्थिक रूप से समझदारी भरा हो सकता है लेकिन लोकतंत्र में बजट का मूल्यांकन केवल भविष्य के सपनों से नहीं, वर्तमान की चुनौतियों से भी होता है।

शिक्षा और रोजगार को जोड़ने वाला 'एजुकेशन-टू-एम्प्लॉयमेंट' मॉडल सरकार की उस सोच को सामने लाता है, जो कक्षा और कार्यस्थल के बीच की खाई को पाटने का दावा करती है। पहली नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए 15,000 रुपये का डीबीटी बोनस और एक करोड़ इंटर्नशिप की घोषणा निश्चित रूप से आकर्षक लगती है। यह कदम युवाओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में सकारात्मक है। लेकिन यहां भी सबसे बड़ा प्रश्न क्रियान्वयन का है। क्या ये इंटर्नशिप वास्तविक कौशल और स्थायी रोजगार की ओर ले जाएंगी या फिर यह योजना सस्ते श्रम तक सीमित रह जाएगी? भारत पहले भी कई बार योजनाओं के आकर्षक नाम और बड़े लक्ष्यों के बावजूद जमीनी स्तर पर कमजोर क्रियान्वयन का अनुभव कर चुका है।

स्किल इंडिया 2.0' के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसी उभरती तकनीकों को क्षेत्रीय भाषाओं में सिखाने की योजना डिजिटल डिवाइड को कम करने की दिशा में अहम कदम है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी युवाओं के लिए यह तकनीकी दुनिया में प्रवेश का द्वार खोल सकता है लेकिन प्रशिक्षकों की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और उद्योग-सहयोग के बिना यह पहल भी सीमित असर तक सिमट सकती है। शिक्षा बजट को लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव सराहनीय है लेकिन बढ़ती छात्र संख्या, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और शोध की जरूरतों के सामने यह राशि अपर्याप्त प्रतीत होती है। मध्यम वर्ग के लिए यह बजट राहत और मायूसी का मिश्रण है। आयकर दरों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन आयकर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में घोषणा अवश्य की गई है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, कर व्यवस्था को जटिल छूटों के जाल से निकालकर सरल और पारदर्शी बनाना, ताकि उपभोग बढ़े और अर्थव्यवस्था में मांग का संचार हो। यह दृष्टिकोण आर्थिक सुस्ती के दौर में उपयोगी हो सकता है।

सरकार ने कुछ चुनिंदा वस्तुओं और क्षेत्रों में कर कटौती कर राहत देने की कोशिश की है। कैंसर और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं का सस्ता होना निसंदेह करोड़ों परिवारों के लिए जीवनरक्षक कदम है। मोबाइल फोन, ईवी बैटरी और सौर पैनलों पर रियायतें हरित ऊर्जा और डिजिटल इंडिया को गति देने के साथ-साथ तकनीक को आम आदमी की पहुंच में लाने का प्रयास हैं। जूते, कपड़े और कुछ घरेलू उपकरणों के सस्ते होने से मध्यमवर्गीय खपत में हल्की तेजी आ सकती है लेकिन दूसरी ओर शराब, खनिज और स्क्रैप पर बढ़े शुल्क से उत्पादन लागत बढ़ने और अंततः उपभोक्ता कीमतों पर असर पड़ने की आशंका भी बनी हुई है। सबसे बड़ा झटका शेयर बाजार में देखने को मिला। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर बढ़े टैक्स ने खुदरा निवेशकों की धारणा को कमजोर किया और बजट के दौरान बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। इससे यह संदेश गया कि सरकार सट्टात्मक गतिविधियों पर सख्ती चाहती है लेकिन इसके दुष्परिणाम अल्पकाल में निवेशकों और बाजार की स्थिरता पर पड़े। यह बजट महंगाई और निवेश के मोर्चे पर एक तरह का विरोधाभास प्रस्तुत करता है, एक ओर खपत बढ़ाने की कोशिश, दूसरी ओर निवेश भावना को झटका।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर ₹12.2 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय सरकार की विकास रणनीति का सबसे मजबूत स्तंभ है। सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, जिनमें मुंबई-पुणे और दिल्ली-वाराणसी जैसे मार्ग शामिल हैं, भारत की कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास की तस्वीर बदल सकते हैं। बेहतर परिवहन से उद्योग, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और रियल एस्टेट को नई गति मिल सकती है।

टियर-2 और टियर-3 शहरों पर फोकस शहरीकरण के असंतुलन को सुधारने की दिशा में सही कदम है। हालांकि, बुनियादी ढ़ांचे पर खर्च का लाभ आम आदमी तक पहुंचने में समय लगता है और तात्कालिक रूप से निर्माण सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी महंगाई का दबाव बढ़ा सकती है। एमएसएमई और व्यापार जगत के लिए बजट में नई संजीवनी दिखाई देती है। 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई ग्रोथ फंड छोटे उद्यमों को पूंजी की कमी से उबार सकता है। महिलाओं के लिए मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये करना महिला उद्यमिता को वास्तविक आर्थिक ताकत देने की दिशा में अहम कदम है। टेक्निकल टेक्सटाइल पर विशेष फोकस भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थान दिला सकता है और मेक इन इंडिया' को व्यावहारिक आधार दे सकता है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह बजट ऐतिहासिक कहा जा सकता है क्योंकि पहली बार कंटेंट क्रिएटर्स और क्रिएटिव इकोनॉमी को औपचारिक मान्यता दी गई है। रील' और रियल' इकोनॉमी के बीच की दीवार लगभग गिर चुकी है। डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, एनीमेशन और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को एमएसएमई जैसा दर्जा मिलने से युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं। हालांकि बौद्धिक संपदा संरक्षण, आय की स्थिरता और नियमन जैसे सवाल भविष्य की बड़ी चुनौतियां बने रहेंगे। स्वास्थ्य और तकनीक के मोर्चे पर बायो-फार्मा 2.0' और सेमीकंडक्टर मिशन पर जोर भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक सोच को दर्शाता है। दवा परीक्षण और अनुसंधान के लिए 1,000 टेस्टिंग साइट्स का नेटवर्क दवाओं की लागत कम कर सकता है। सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भरता भारत को वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत बनाएगी। रक्षा बजट में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है लेकिन नई नीतिगत घोषणाओं के अभाव में बाजार की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकी।

इस पूरे बजट की सबसे बड़ी कमी किसानों को लेकर किसी ठोस और नई घोषणा का न होना है। कृषि क्षेत्र अभी भी महंगाई, लागत और आय की अनिश्चितता से जूझ रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना समग्र विकास अधूरा रहेगा, यह सच्चाई इस बजट में अपेक्षाकृत कम झलकती है। कुल मिलाकर, बजट 2026-27 संतुलित प्रयास माना जा सकता है। यह न तो लोकलुभावन है और न ही कठोर सुधारवादी। सरकार ने भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए दिशा स्पष्ट की है लेकिन महंगाई, रोजमर्रा का खर्च और आय की सुरक्षा जैसी आम आदमी की तात्कालिक चिंताओं पर सीधी राहत सीमित है। यह बजट आम नागरिक को तुरंत सुकून देने के बजाय धैर्य रखने की सलाह देता है। आने वाले समय में इसका मूल्यांकन इस बात से होगा कि इसके वादे कितनी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ जमीन पर उतरते हैं। अब असली परीक्षा बजट भाषण की नहीं बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन की है।

नजरिया

धातुओं की दुनिया में अस्थिरता का खेल

प्रो. आरके जैन अरिजीत

सोने और चांदी की कीमतों में आई हालिया तीखी गिरावट ने देश ही नहीं, बल्कि वैश्विक वित्तीय बाजारों की धड़कन बढ़ा दी है। जिन कीमती धातुओं को अब तक आर्थिक संकट, युद्ध और मंदी के दौर में सबसे सुरक्षित आश्रय माना जाता था, वही अचानक कमजोरी का प्रतीक बनती दिखीं। निवेशक भ्रमित हैं, ज्वैलरी कारोबारियों की रणनीतियां गड़बड़ा गई हैं और आम उपभोक्ता असमंजस में है। यह गिरावट ऐसे समय पर सामने आई है जब भारत में बजट को लेकर अटकलें तेज हैं और विश्व अर्थव्यवस्था एक नए पुनर्संतुलन के दौर से गुजर रही है। असली सवाल सिर्फ कीमतों के गिरने का नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति का है जो बाजार की दिशा तय कर रही है और आने वाले समय की तस्वीर बना रही है।

कुछ ही सप्ताह पहले तक सोना और चांदी रिकॉर्ड स्तरों पर चमक रहे थे। लगातार बढ़ते भावों ने निवेशकों के मन में यह धारणा बना दी थी कि इन धातुओं की कीमतें अब पीछे मुड़कर देखने वाली नहीं हैं। हर हल्की गिरावट को खरीदारी का सुनहरा अवसर समझा जा रहा था। लेकिन बाजार की प्रकृति स्थिर नहीं होती। अचानक मुनाफावसूली का दबाव बढ़ा और तेजी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। भाव इतनी तेजी से नीचे आए कि लंबे समय से बनी तेजी की कहानी एक झटके में कमजोर पड़ती नजर आई। यह गिरावट सामान्य सुधार नहीं, बल्कि बाजार के आत्ममंथन का संकेत बन गई।

वायदा बाजार में इस बदलाव की तस्वीर और भी स्पष्ट दिखाई दी। एमसीएक्स पर सोने और चांदी के अनुबंधों में जोरदार बिकवाली हुई, जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। अंतरराष्ट्रीय बाजार भी इस दबाव से अछूते नहीं रहे। कॉमेक्स पर सोना नीचे फिसला, जबकि चांदी ने अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा कमजोरी दिखाई। विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय से चली आ रही तेज तेजी ने बाजार को ओवरबॉट स्थिति में पहुंचा दिया था। जब कीमतें वास्तविक मांग और आपूर्ति से काफी आगे निकल जाती हैं, तब संतुलन बहाल होना तय होता है। इस बार यह संतुलन तेजी से और बड़े पैमाने पर आया।

इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की नीतियों को सबसे प्रभावशाली कारक माना जा रहा है। वहां की मौद्रिक नीति से जुड़े संकेतों ने डॉलर को नई मजबूती दी, जिसने वैश्विक बाजारों की दिशा बदल दी। डॉलर जैसे ही मजबूत होता है, वैसे ही सोना और चांदी जैसी डॉलर आधारित संपत्तियों पर दबाव बढ़ने लगता है। विदेशी निवेशकों ने जोखिम घटाने के लिए सुरक्षित निवेश से दूरी बनानी शुरू कर दी और पूंजी का रुख दूसरी परिसंपत्तियों की ओर मोड़ दिया। अमेरिका के फैसले केवल उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनकी गूंज सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सुनाई देती है और भारत जैसे देशों तक असर पहुंचाती है।

वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं, लेकिन हालिया घटनाक्रम ने निवेशकों की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से बदल दिया है। अब बाजार युद्ध और टकराव की आशंकाओं से ज्यादा ब्याज दरों की दिशा, डॉलर की मजबूती और प्रमुख आर्थिक आंकड़ों पर प्रतिक्रिया दे रहा है। केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद में आई सुस्ती ने भी मांग की धार को कमजोर किया है। चीन और भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देशों में भौतिक मांग अब भी मौजूद है, लेकिन लगातार ऊंचे भावों के बाद वहां भी सतर्कता का भाव बढ़ा है। वैश्विक कर्ज का बढ़ता बोझ और आर्थिक असंतुलन भले ही दीर्घकाल में सोने के पक्ष में खड़े हों, पर अल्पकाल में डॉलर की ताकत ने बाजार पर अपना दबदबा कायम कर लिया है।

भारत में इस गिरावट का असर अपेक्षाकृत अधिक तीव्र रहा, जिसका कारण आयात पर लगने वाले ऊंचे शुल्क और कर संरचना है। बजट से पहले यह बहस तेज हो गई है कि सरकार सोने और चांदी पर लगने वाले शुल्क में बदलाव कर सकती है। यदि शुल्क में कटौती होती है तो कीमतों में और नरमी आने की संभावना है, जिससे मांग को नई ऊर्जा मिल सकती है। इससे तस्करी पर अंकुश लगेगा और संगठित बाजार को मजबूती मिलेगी। इसके विपरीत, यदि राजस्व दबावों के चलते शुल्क बढ़ाया गया तो कीमतों पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है और उपभोक्ताओं की जेब पर असर और गहरा हो जाएगा। यह गिरावट किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि वैश्विक नीतिगत बदलावों और आर्थिक संकेतों का स्वाभाविक नतीजा प्रतीत होती है। पिछले वर्षों में जब अनिश्चितता, महामारी और भू-राजनीतिक तनाव चरम पर थे, तब सोना और चांदी निवेशकों की पहली पसंद बने। अब जैसे ही वैश्विक नीतियों का रुख धीरे-धीरे बदलता दिख रहा है, बाजार भी नई दिशा तलाश रहा है। भारत में रुपये की कमजोरी, बढ़ता व्यापार घाटा और सोने का बढ़ता आयात इस परिदृश्य को और जटिल बनाते हैं। सरकार के सामने चुनौती यह है कि वह आर्थिक विकास को गति देते हुए वित्तीय स्थिरता और बाहरी संतुलन को भी बनाए रखे।

निवेशकों के दृष्टिकोण से यह समय घबराहट का नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण निर्णय लेने का है। तेज गिरावट के बाद कीमतें ऐसे स्तरों के करीब पहुंच सकती हैं जो लंबी अवधि के निवेश के लिए आकर्षक माने जाते हैं। मुद्रास्फीति का दबाव, भू-राजनीतिक जोखिम और वैश्विक मुद्रा व्यवस्था में संभावित बदलाव जैसे कारक आने वाले वर्षों में फिर से सोने और चांदी को समर्थन दे सकते हैं। हालांकि निकट भविष्य में उतार-चढ़ाव बना रहना तय है। ऐसे में जल्दबाजी के बजाय चरणबद्ध निवेश, संतुलित पोर्टफोलियो और जोखिम प्रबंधन की रणनीति अपनाना ही समझदारी भरा कदम माना जा रहा है।

कुल मिलाकर सोने और चांदी में आई मौजूदा कमजोरी को किसी एक देश, एक नीति या एक घटना के दायरे में बांधकर देखना वास्तविकता को अधूरा समझना होगा। अमेरिका की मौद्रिक रणनीतियां, डॉलर की बढ़ती ताकत और बदलती वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां मिलकर इस पूरे परिदृश्य की रूपरेखा तय कर रही हैं। भारत के संदर्भ में आने वाला बजट इस दिशा में निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। यदि नीतिगत स्तर पर राहत और संतुलन का संकेत मिला तो बाजार को स्थिरता का सहारा मिलेगा, लेकिन यदि दबाव बरकरार रहा तो कमजोरी कुछ समय और खिंच सकती है। इतिहास यही सिखाता है कि कीमती धातुएं अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के बाद अंततः अपनी चमक लौटाती हैं, शर्त सिर्फ इतनी है कि निवेशक धैर्य, अनुशासन और दूरदर्शिता के साथ निर्णय लें।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टेंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

पीजीआईएमईआर के चिकित्सकों ने घातक सल्फ़ास विषाक्तता की काट खोजी

चंडीगढ़/भाषा

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा एंव अनुसंधान (पीजीआईएमईआर) के चिकित्सकों ने एल्युमिनियम फॉस्फाइड (जिसे आमतौर पर सल्फास के नाम से जाना जाता है) नामक घातक कीटनाशक से होने वाली विषाक्तता के उपचार में एक बड़ी सफलता हासिल की है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

पीजीआईएमईआर ने एक बयान में बताया कि संस्थान के आंतरिक चिकित्सा विभाग द्वारा किए गए अनुसंधान में पहली बार प्रदर्शित किया गया कि सल्फास की विषाक्तता के इलाज में ''इंट्रावेनस लिपिड इमल्शन'' प्रभावी जीवन रक्षक तरीका है।

बयान के मुताबिक इन महत्वपूर्ण निष्कर्षों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पत्रिका 'यूरोपियन रिव्यू ऑफ मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल साइंसेज' में प्रकाशित किया गया है, जिससे इस अध्ययन को वैश्विक मान्यता मिली है।

पीजीआईएमईआर के मुताबिक '' अध्ययन के निष्कर्ष स्पष्ट होता कि इस इलाज पद्धति को तुरंत इस्तेमाल करने से एल्यूमीनियम फॉस्फाइड विषाक्तता के इलाज में अहम बदलाव आ सकता है।''

इसमें कहा गया, ''अध्ययन के परिणाम बेहद उत्साहजनक थे। जिन रोगियों को मानक चिकित्सा उपचार के अतिरिक्त अंतःशिरा लिपिड इमल्शन दिया गया, उनमें मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी देखी गई, साथ ही गंभीर चयापचय अम्लता का तेजी से सुधार हुआ, हेमोडायनामिक स्थिरता में सुधार हुआ तथा सदमे और हृदय संबंधी जटिलताओं से पीड़ित रोगियों सहित गंभीर रूप से बीमार रोगियों में बेहतर परिणाम प्राप्त हुए।''

चिकित्सकों के मुताबिक इस नवीन उपचार का एक प्रमुख लाभ इसकी व्यावहारिकता है, क्योंकि 'इंट्रावेनस लिपिड इमल्शन' सस्ता है, व्यापक रूप से उपलब्ध है, और पहले से ही भारत भर के अधिकांश अस्पतालों में, जिनमें जिला अस्पताल और परिधीय स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं, स्टॉक में मौजूद है। बयान में कहा गया है कि इसकी कम लागत और आसानी से उपलब्धता के कारण, इस चिकित्सा पद्धति में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी लोगों की जान बचाने की क्षमता है, जहां सेल्फ़ोस विषाक्तता का बोझ सबसे अधिक है और उन्नत गहन देखभाल तक पहुंच अक्सर सीमित होती है।

संस्थान ने कहा कि कम लागत और आसानी से उपलब्धता के कारण, इस चिकित्सा पद्धति में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी लोगों की जान बचाने की क्षमता है, जहां सेल्फ़ोस विषाक्तता के मामले सबसे अधिक आते हैं और उन्नत गहन देखभाल तक पहुंच अक्सर सीमित होती है। इसमें कहा गया, ''एल्युमिनियम फॉस्फाइड विषाक्तता एक गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्यों में, जहां अनाज को संरक्षित रखने के लिए इस यौगिक का व्यापक इस्तेमाल होता है। इसलिए इन क्षेत्रों के लिए एक प्रभावी, किफायती और साक्ष्य-आधारित उपचार की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है।'' बयान के अनुसार, यह अध्ययन पीजीआईएमईआर के आंतरिक चिकित्सा विभाग के डीन (अकादमिक), प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ. संजय जैन के मार्गदर्शन में किया गया था।

'बैटल ऑफ गलवान' में अपने लुक की आलोचनाओं पर सलमान ने दी प्रतिक्रिया

मुंबई/भाषा

अभिनेता सलमान खान ने आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में अपने लुक को लेकर हो रहीं आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा है कि वह एक कर्नल की भूमिका निभा रहे हैं और उनका लुक किरदार के अनुरूप है।

सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक 'फैन अकाउंट' पर शुक्रवार शाम को सूरत में आयोजित इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (आईएसपीएल) के कार्यक्रम का सलमान खान का वीडियो साझा किया गया।

वीडियो में खान (60) पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर मोहम्मद कैफ से बातचीत करते नजर आए। कैफ ने मजाकिया अंदाज में खान से कहा कि वह पिछले महीने खान के जन्मदिन पर जारी फिल्म के पहले टीजर में दिखाए गए पोज को दोहराएं।

सलमान खान ने वही पोज दिया और फिर हंसी-मजाक के अंदाज में आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अब किसी को ये समझ में आता है कि ये रोमांटिक लुक है लेकिन कर्नल हूं भैया और ये कर्नल का लुक है, जो समझता है कि अपनी टीम वालों को, अपने जवानों को कैसे हौसला देना है। उन्होंने कहा,

इस सबका कोई मतलब नहीं है, इस लुक का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही चलता आया है और ऐसे ही चलता रहेगा, आप सबकी दुआ से।

बैटल ऑफ गलवान फिल्म 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुए संघर्ष पर आधारित है और इसका निर्देशन शूटआउट एट लोखंडवाला के निर्देशक अपूर्व लाखिया ने किया है। फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

पहला टीज़र जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ यूज़र्स ने सलमान खान के हेयरस्टाइल, दाढ़ी और पूरे लुक का मजाक उड़ाया था।

कई लोगों ने कहा कि वह वास्तविक सैन्य झड़प पर आधारित फिल्म और एक सैन्य अधिकारी के किरदार के लिहाज से खान का लुक बहुत सॉफ्ट या रोमांटिक नजर आ रहा है।

फिल्म में सलमान खान बी. संतोष बाबू की भूमिका निभा रहे हैं, जिन्होंने 16 बिहार रेजिमेंट के 19 अन्य जवानों के साथ गलवान संघर्ष के दौरान देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे।

हड्डियों के लिए अच्छी है रागी इडली : समीरा रेड्डी

मुंबई। मशहूर अभिनेत्री समीरा रेड्डी अपनी हेल्थ को लेकर काफी सक्रिय रहती हैं। वे हमेशा हेल्दी फूड खाने और रोजाना एक्सरसाइज करने पर जोर देती हैं। इसी के साथ ही वे फैंस के लिए अक्सर हेल्दी रेसिपी शेयर भी करती रहती हैं। शनिवार को अभिनेत्री ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया।

इस वीडियो में उन्होंने घर पर नरम और फ्लफी रागी इडली बनाने का पूरा तरीका स्टेप-बाय-स्टेप बताया है। साथ ही, उन्होंने महिलाओं के लिए इस डिश के फायदे भी बताए हैं। वीडियो में अभिनेत्री रेसिपी बनाते हुए कहती हैं, सबसे पहले 1/2 कप उड़द दाल को 4 घंटे भिगो दें और रवा को 1 घंटे भिगोकर रखें। अब उड़द को पीसकर बारीक पेस्ट बना लें। इसमें भीगा हुआ रवा (बिना पीसे) मिलाएं। अब एक पैन में घी गर्म करके करी पत्ते, हींग, उड़द दाल, जीरा और राई का तड़का लगाएं। इसमें रागी का आटा डालकर 1 मिनट तक भूनें। इस मिश्रण को इडली बैटर में मिलाएं। फिर दही, थोड़ा बेकिंग सोडा और नमक डालकर अच्छे से फेंट लें। बैटर को 20 मिनट के लिए ढककर रख दें। इडली मोल्ड्स पर घी लगाकर बैटर भरें और 10-15 मिनट तक स्टीम करें। गरमा-गरम नरम रागी इडली तैयार।

अभिनेत्री ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में इसके खाने के फायदे के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए रागी इडली क्यों फायदेमंद है। उन्होंने लिखा, रागी कैल्शियम से भरपूर होती है, जो हड्डियों को मजबूत रखती है। इसमें हाई फाइबर होता है, जो पेट की सेहत और हार्मोन बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही, यह ब्लड शुगर को स्थिर रखता है, जिससे एनर्जी लेवल संतुलित रहता है। यह डिश हर कौर में आपको एनर्जेटिक, संतुलित और पोषित महसूस कराती है। सुश्रुत संहिता और आयुर्वेद के अनुसार, रागी एक पौष्टिक, शीतल और वात-पित्त शामक अनाज है। यह हड्डियों को मजबूत करने, मधुमेह को नियंत्रित करने और पाचन में सुधार करने में सहायक है।

फिल्म 'गोदान' के निर्माता-निर्देशक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात

लखनऊ/भाषा। गो संरक्षण, भारतीय संस्कृति में उसके महत्व और पंचगव्य आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर बनाई गई फिल्म 'गोदान' के निर्माता-निर्देशक ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक, इस अवसर पर फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक विनोद चौधरी ने कहा कि देश में गोरक्षा को लेकर सबसे व्यापक, ठोस और जमीनी स्तर पर कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है और इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट दृष्टिकोण और प्रतिबद्ध नेतृत्व है।बयान के अनुसार, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश में गो तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं।इसमें कहा गया कि गोवंश के प्रति मुख्यमंत्री के स्नेह और गो संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में साढ़े सात हजार से अधिक गो आश्रय स्थल बनाए गए हैं।बयान में कहा गया कि विनोद चौधरी द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म 'गोदान' छह फरवरी को देशभर में रिलीज होगी। निर्माता ने मुख्यमंत्री को फिल्म की विषयवस्तु, उद्देश्य और सामाजिक संदेश से अवगत कराया।फिल्म निर्माता विनोद चौधरी ने कहा कि आज देश में गोरक्षा के क्षेत्र में जो ठोस कार्य दिखाई दे रहा है, उसका सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में गोशालाओं का विस्तार, निराश्रित गोवंश की व्यवस्था, तस्करी पर सख्ती और गो संरक्षण को शासन की प्राथमिकता बनाना, ये सभी कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संभव हो पाए हैं। फिल्म निर्माता ने मुख्यमंत्री से फिल्म को कर-मुक्त किए जाने की अपेक्षा भी जताई। उनका कहना था कि यह फिल्म किसी एक जाति, धर्म या वर्ग की नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक के लिए है और विशेषकर युवा पीढ़ी को यह फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान विनोद चौधरी (निर्माता), शांतनु शुक्ला (प्रचार-प्रसार प्रमुख), डॉ. कपिल त्यागी (सीएमडी, यथार्थ अस्पताल, नोएडा) और नवल किशोर उपस्थित रहे।

'द केरल स्टोरी 2' के टीजर को मिला संत-समाज का समर्थन

अयोध्या/एजेन्सी

कामाख्या नारायण सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' का टीजर आते ही छा गया है, जिसमें हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा कर जबरन धर्मांतरण कराने की कहानी को मार्मिक तरीके से दिखाया है। टीजर रिलीज के साथ फिल्म का विरोध भी शुरू हो गया है लेकिन देश का संत-समाज फिल्म की सराहना कर रहा है। संत- समाज का कहना है कि फिल्म का विरोध करने वाले महा पापी हैं। अयोध्या के जगतगुरु परमहंस आचार्य ने 'द केरल स्टोरी 2' के टीजर पर आईएएनएस से बातचीत में कहा, लव जिहाद अपने चरम पर है, और एक भी हिंदू लड़की सुरक्षित नहीं है। लड़की के पैदा होने का मतलब है कि वे जिहादियों के निशाने पर आ गई हैं। दिल्ली में भी 6 साल की बच्ची के साथ विशेष समुदाय के तीन लोगों ने दुष्कर्म किया है, ऐसे में जो लोग 'द केरल स्टोरी 2' का विरोध कर रहे हैं, वे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये लोग घृणित सोच वाले लोग हैं, जो महिला के प्रति गंदी मानसिकता रखते हैं। लव जिहाद पर सरकार को अब बहुत कठोर कानून बनाने की जरूरत है।

'द केरल स्टोरी 2' के टीजर पर सीताराम दास महाराज ने कहा, 'द केरल स्टोरी 2' वास्तविकता को दिखाने का काम कर रही है। मैं इसका विरोध करने वालों से पूछना चाहता हूं कि सच दिखाने में क्या अपराध है? हमारी बेटियां जो डॉक्टर बनना चाहती हैं, इंजीनियर या फिर जज बनना चाहती हैं, उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर उनका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, वो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं और उन्हें देश में रहने का हक नहीं है। नासिक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने इस मामले पर कहा, पहली फिल्म ने पूरी सच्चाई दिखाई थी कि जिहादी हिंदू बहन-बेटियों के साथ क्या करते हैं। ये नाना प्रकार के जिहाद देश में सालों से फैलाते हैं। मेरा सभी सनातनियों से कहना है कि हमें इन जिहादियों से खुद को बचाना होगा। वे कभी हमारे नहीं हो सकते। हमें द केरल स्टोरी 2 को पूरा देखना चाहिए। फिल्म जिहादियों का पर्दाफाश करने के लिए बनाई गई है।

वहीं, ऋषिकेश के श्री भरत मिलाप आश्रम के प्रमुख स्वामी नारायण दास ने सच्चाई को साहसपूर्वक उजागर करने के लिए 'द केरल स्टोरी 2' की प्रशंसा की और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, मैं फिल्म नहीं देखता, पर मैंने इस फिल्म के बारे में बहुत सुना है। किसी का जबरन धर्मांतरण करना महापाप है और फिल्म जिहादियों के धर्मांतरण को दिखाती है कि कैसे वे हमारी बच्चियों को शिकार बनाते हैं। इस मानसिकता को समर्थन करने वाला भी पापी है।

बजट सत्र

नई दिल्ली में टीएमसी सांसद जून मालिया और महुआ मोइत्रा रविवार को नई दिल्ली में संसद परिसर में 'यूनियन बजट 2026-27' पेश होने के बाद संसद से बाहर आते हुए।

विशाल भारद्वाज ने अरिजीत सिंह के पार्श्व गायन छोड़ने के फैसले को 'अनुचित' बताया

नई दिल्ली/भाषा

फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर एक नोट साझा कर प्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंह से पार्श्व गायन से संन्यास लेने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। भारद्वाज ने उनके इस फैसले को अनुचित और अस्वीकार्य बताया है।

भारद्वाज ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म 'ओ रोमियो' के अगले गाने के लिए सिंह के साथ अपने हालिया संगीत साधना का एक वीडियो साझा किया। इस नए गाने के बोल इश्क का फीवर है। शाहिद कपूर अभिनीत फिल्म 'ओ रोमियो' 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

फिल्मकार ने अरिजीत के साथ कई फिल्मों में काम किया है। उनका कहना है कि उन्हें गायक के इस फैसले की जानकारी नहीं थी।

भारद्वाज ने पोस्ट में लिखा, अरिजीत कुछ दिन पहले तक, जब हम इस गाने पर संगीत साधना कर रहे थे (तब आप वीडियो की शूटिंग कर रहे थे)। मुझे नहीं पता था कि ये आपके साथ मेरा आखिरी फिल्मी गाना होगा। यह अनुचित है अपना संन्यास वापस लें, यह स्वीकार्य नहीं है।

इस सप्ताह की शुरुआत में अरिजीत सिंह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लंबी पोस्ट के जरिए पार्श्व गायन से संन्यास लेने की घोषणा की थी। उन्होंने लिखा था, नमस्ते, आप सभी को नया साल मुबारक। मैं आप सभी श्रोताओं को इतने वर्षों तक मुझे इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब से मैं पार्श्व गायक के रूप में कोई नया काम नहीं करूंगा। मैं इसे यहीं समाप्त कर रहा हूं। यह एक शानदार यात्रा थी।

फिल्मों में नहीं चली किस्मत तो बिजनेस में हाथ आजमा रहीं अमृता अरोड़ा

नई दिल्ली/एजेन्सी

कभी अपने मूव्स से सबको दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री, आज शोबिज का हिस्सा बनकर जिंदगी जी रही हैं। हम बात कर रहे हैं अमृता अरोड़ा की, जिन्होंने शादी के बाद फिल्मी पर्दे से दूरी बना ली। लेकिन आज भी ग्लैमरस पार्टी का हिस्सा बनती हैं। अभिनेत्री शनिवार को अपना जन्मदिन मना रही हैं। 31 जनवरी 1978 को मुंबई में जन्मीं अमृता अरोड़ा भले ही फिल्मी पर्दे का हिस्सा रहीं, लेकिन अपनी बहन मलाइका अरोड़ा की तरह नाम नहीं बना पाई। मलयाली कैथोलिक से ताल्लुक रखने वाली अभिनेत्री फिल्मों में कदम रखने से पहले टीवी का बड़ा चेहरा हुआ करती थीं। उन्होंने 17 साल की उम्र में एमटीवी के 'हाउसफुल' और 'चिल आउट' जैसे शोज को होस्ट किया था और वीजे भी रही थीं। अमृता की पहली फिल्म साल 2002 में आई 'कितने दूर कितने पास' थी, जिसके बाद उन्होंने 'आवारा पागल दीवाना', 'गर्लफ्रेंड', 'एक और एक ग्यारह', 'मुझसे शादी करोगी', 'गोलमाल रिटर्न' और 'कमबख्त इश्क' जैसी फिल्मों में काम किया और कई फिल्मों में स्पेशल अपीरियंस भी दी। अमृता अरोड़ा के करियर की ज्यादातर फिल्में औसत रहीं। फिल्मों के जरिए किस्मत को चमकाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन साल 2009 में उन्होंने शकील के साथ शादी करके फिल्मों से दूरी बना ली। अभिनेत्री की शादी भी विवादों में रही क्योंकि शकील अमृता की सहेली के ही पति हुआ करते थे। हालांकि, कभी भी अमृता ने विवादों पर जवाब नहीं दिया, आज भी अपने पति और दो बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। अमृता भले ही फिल्मों से दूर हैं, लेकिन करीना कपूर खान से उनकी दोस्ती बहुत खास हैं, जो उन्हें शोबिज का हिस्सा बनाए रखती हैं। अमृता, करीना कपूर खान और मलाइका अरोड़ा की तिकड़ी हमेशा सोशल मीडिया पर छाई रहती है।

भारतीय महिलाओं के अंदर 'सुपरपावर' होती है : रानी मुखर्जी

नई दिल्ली/एजेन्सी

अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'मर्दानी 3' में दमदार किरदार निभाकर सुर्खियां बटोर रहीं रानी मुखर्जी का मानना है कि महिलाएं ही असली हीरो होती हैं और महिलाएं सशक्त हैं तो देश भी मजबूत रहेगा। अभिनेत्री ने कहा है कि वह हमेशा भारतीय महिलाओं को सबसे अच्छी रोशनी में दिखाना चाहती हैं। अपनी फिल्मों के माध्यम से उन्होंने मजबूत, साहसी और सशक्त महिलाओं के किरदार निभाए हैं, जो समाज में प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। रानी ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा, जब से मैंने इस इंडस्ट्री में काम शुरू किया है, मैंने हमेशा भारतीय महिलाओं को सबसे अच्छी रोशनी में दिखाने की कोशिश की है। चाहे वह पत्रकार हों, पुलिस अधिकारी हों, टीचर हों या हाउस वाइफ, मेरे लिए वे असली हीरो हैं, असली मर्दानी हैं। मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूं कि भारतीय महिलाएं कितनी खास हैं, कितनी मजबूत और सशक्त हैं।

उन्होंने बताया कि महिलाओं का सशक्तीकरण देश की ताकत से सीधे जुड़ा है। रानी ने कहा, जब भारतीय महिलाएं सशक्त होंगी, तभी हमारा देश मजबूत बन पाएगा। इसीलिए मेरी फिल्मों का चुनाव हमेशा इसी सोच के साथ रहा है। अपने करियर की शुरुआत से ही रानी ने ऐसे रोल चुने हैं, जो महिलाओं की ताकत को उजागर करते हैं। पहली फिल्म 'राजा की आएगी बारात' में रेप सर्वाइवर का किरदार, 'मेहंदी' में सामाजिक अन्याय से लड़ने वाली महिला, 'हिचकी' में टॉरेट सिंड्रोम से जूझ रही टीचर, 'मर्दानी' सीरीज में निडर पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय, और 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' में बच्चों के लिए पूरे देश से लड़ने वाली मां देबिका चटर्जी, इन सभी किरदारों ने महिलाओं की हिम्मत और संघर्ष को दिखाया है।

रानी ने कहा, हर भारतीय महिला के अंदर एक अनोखी ताकत या 'सुपरपावर' होती है। मैं दिखाना चाहती हूं कि भारतीय महिलाएं कितनी खास हैं। वे अपने कर्तव्यों को खूबसूरती से निभाती हैं, पारिवारिक जीवन को ग्रेस के साथ बैलेंस करती हैं। यही यूनिफॉर्म वाली महिलाओं और पावरफुल पदों पर बैठी महिलाओं का सबसे प्रेरणादायक पहलू है। वह रोजमर्रा की जिंदगी में चुनौतियों का सामना करने वाली उन महिलाओं की तारीफ करती हैं जो हिम्मत से आगे बढ़ती रहती हैं। नेशनल अवॉर्ड विजेता रानी ने कहा, ये महिलाएं अपने अंदर बहुत ज्यादा ताकत लेकर रोज की जिंदगी जीती हैं और रास्ते की हर मुश्किल को पार करती हैं। मैं उन सभी से बहुत ज्यादा प्रेरित हूं। मेरे निभाए हर किरदार से मुझे प्रेरणा मिली है। उन्होंने 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' की देबिका का उदाहरण देते हुए कहा कि ये पावरफुल और मजबूत महिलाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। एक आर्टिस्ट के तौर पर रानी का मानना है कि उनका रोल इन महिलाओं को जिंदा करना है, ताकि दुनिया भर के लाखों लोग देख सकें कि वे क्या करती हैं और कितनी प्रेरणादायक हैं।

गौसेवा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के जिनकुशलसूरी जैन दादावाड़ी ट्रस्ट बसवनगुड़ी के तत्वावधान में जिनदत्तकुशलसूरी जैन सेवा एवं संगीत मंडल के सदस्यों द्वारा रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रमों की श्रृंखला में पूर्णिमा के मौके पर रविवार को जीवदया कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंडल के महामंत्री ललित डाकलिया, जीवदया संयोजक भरत कोठारी, कुनाल मरलेचा, रणजीत मेहता, विकास बच्छावत, राजा बाबू पारख ने दोड्डनिकुंदी गौशाला महादेवपुरा में गायों को हरा चारा खिलाया तथा गौशाला में सहयोग दिया ।

विशुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म हमेशा बड़ा पुण्य का अर्जन करता है : साध्वी भव्यगुणाश्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के सदाशिवनगर में विराजित साध्वी भव्यगुणाजी ने कहा कि जिस प्रकार वटवृक्ष का बीज छोटा होते हुए भी उससे बड़ा आकार पाने वाला अंकुर निकलता है, उसी प्रकार जिसका हृदय विशुद्ध है उसका थोड़ा किया हुआ पुण्यकर्म भी बड़े पुण्य का अर्जन करता है। दान, शील, तप, भाव, धर्म में भावधर्म सबसे अधिक महत्वशाली है। संसार में धार्मिक और सभी क्रियाएं सभाव से सफल होती हैं, अतः भाव धर्म को स्वर्ग रूपी महल पर चढ़ने की निसरनी (सीढ़ी) और भवसागर से पार होने की नौका के समान माना गया है, इसलिए कोई भी धर्मानुष्ठान किया जाए उसमें भावविशुद्धता को स्थान देना चाहिए, तभी उसका वास्तविक फल मिल सकता है।ङ्कसाध्वी शीतलगुणाजी ने कहा कि जिंदगी सुकून से जीनी है तो एक बात जरूर गांठ बांध लें कि किसी से बदला लेने से ज्यादा खुद को बदल लेने में मजा है। अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, क्योंकि उसका कार्य खुद उसे सम्मान का पात्र बना देता है। साध्वीश्री ने कहा कि जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के लिए भी करें। आप जो देते हैं, वही हज़ार गुणा होकर लौट आता है।

अन्नदान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु की 'सेकेंड इनिंग्स' संस्था की ओर से रविवार को केआर रोड स्थित वाणी विलास हॉस्पिटल के पास 28वें पूनम अन्नदान का आयोजन किया गया। गौतमचंद, विक्रमकुमार धारीवाल व तेजराज आनंदकुमार मालानी परिवार के सौजन्य से आयोजित इस अन्नदान में चेयरमैन विनय मरलेचा, महावीर जैन, राजेश मलानी, पूनम अभिषेक, मंजूनाथ राव और उपाध्यक्ष गौतमचंद धारीवाल ने अपने हाथों से जरूरतमंदों को भोजन कराया।

बागलूरु मैन रोड कट्टिगनहल्ली भगवामय रंग में रंगी गई

'विराट हिन्दू समाजोत्सव' में उमड़ा हिन्दू जनसैलाब

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर की हिन्दू समाजोत्सव समिति के तत्वावधान में रविवार को दोपहर 3 बजे से विराट हिन्दू समाजोत्सव कार्यक्रम का आयोजन यलहंका क्षेत्र के अंतर्गत कट्टिगनहल्ली स्थित बागलूर मैन रोड पर यशस्वी स्कूल के पास चालुक्या ग्राउंड पर किया गया जिसमें बड़ी संख्या में हिन्दू समर्थक लोग उपस्थित थे। इस मौके पर श्री शिवानंदा बृहनमाता मठ गदग के जगदगुरु श्री सदाशिव महास्वामीजी के पावन सान्निध्य में, मुख्य अतिथि के रूप में कर्नाटक दक्षिण प्रांत सभा सम्पर्क प्रमुख हरीश व हिन्दू समाजोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने गौपूजा कर भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस हिन्दू समावेश को संबोधित करते हुए सभी अतिथियों ने हिन्दुओं को एकजुट होने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि यदि हिन्दू समाज एक रहेगा तो मजबूत रहेगा। कार्यक्रम से पहले एयरफ़ोर्स सेन्टर के पास स्थित सर्कल से हिन्दू समाजोत्सव रैली का आयोजन किया गया। रैली बागलूरु रोड से होते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय व उत्तरभारतीय समाज के लोग शामिल हुए। सभी लोग अपने हाथों में भगवा झंडा लेकर व महिलाएं सिर पर कलश धारण कर शामिल हुए। रैली में अनेक बैंड, झांकियां व लोक कलाकार शामिल थे। पूरी बागलूरु रोड भगवा रंग के कपड़े, दुप्पटा व झंडों से अटी पड़ी थी। प्रमुख वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में स्पष्ट कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोग जो भारत में रहते हुए इसकी संस्कृति और देश को प्यार करते हैं, जो भारत माता का सम्मान करते हैं वे सब हिंदू हैं। इन हिंदुओं को विभिन्न देवताओं के नाम पर, विभिन्न जातियों के नाम पर, भाषा और प्रांत के नाम पर बाँटकर राजनीति करने वाले लोग देश को कमजोर करने में लगे हैं। ऐसे विभाजनकारी ताक़तों से सावधान रहते हुए सभी हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। हमको जातियों में विभाजित करने वालों की साज़िश को समझना होगा।

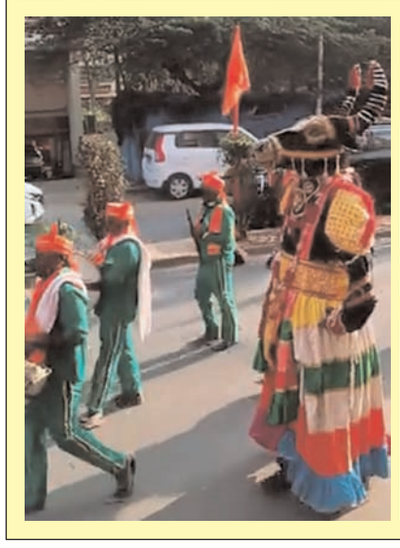

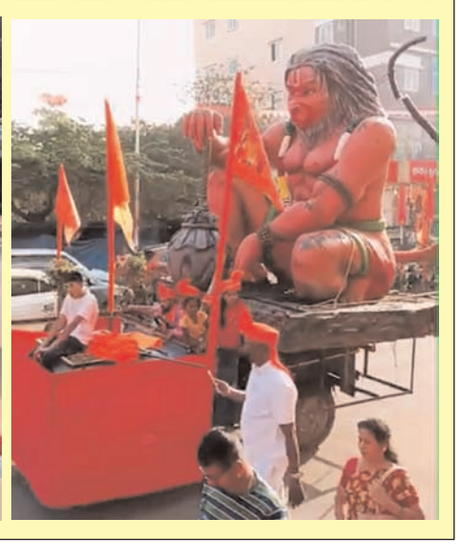

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

गुरु दर्शन

तेरापन्थ सभा गांधीनगर बेंगलूरु के अध्यक्ष पारसमल भंसाली के नेतृत्व में सभा के पदाधिकारियों ने तिरुपुर में विराजित साध्वीश्री पावनप्रभाजी के दर्शन किए। ज्ञातव्य है कि साध्वीश्री पावनप्रभाजी का चातुर्मास बेंगलूरु गांधीनगर में घोषित है। पदाधिकारियों ने साध्वी जी से निवेदन किया कि आप शीघ्र बेंगलूरु पधारें ताकि सभी क्षेत्रों की सार सम्भाल हो सके। साध्वीश्री ने शीघ्र बेंगलूरु आने का आश्वासन देते हुए आशीर्वाद दिया। इस मौके पर तेरापंथ ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश बाबेल, कोषाध्यक्ष प्रकाश कटारिया, संगठन मंत्री राजेन्द्र बाफना साथ में थे।

जसवन्तराज छाजेड़

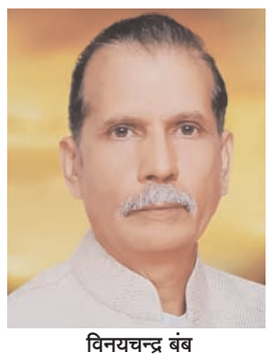

विनयचन्द्र बंब

जसवन्तराज बने राजाजीनगर श्रावक संघ के नए अध्यक्ष, विनयचन्द्र बने सचिव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, राजाजीनगर की वार्षिक सभा में वर्ष 2026-27 के लिए नई कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया जिसमें सर्वसम्मति से जसवन्तराज छाजेड़ को अध्यक्ष, मीठालाल लोढ़ा को उपाध्यक्ष, विनयचन्द्र बंब को मंत्री, प्रकाशचन्द भलगट को सहमंत्री व पारसमल भलगट को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कार्यकारिणी समिति में भागचन्द गुगलिया, चेतनकुमार रेदासनी, धीरजराज नाहर, गौतमचन्द मेहता, ज्ञानचन्द लोढ़ा, हुकमीचन्द भलगट, कनकराज चोरड़िया, मदनलाल गांधी, महेन्द्रकुमार धोका, राकेशकुमार दलाल, रामचन्द्र गुंदेचा , सम्पतराज चाणोदिया, शान्तिलाल चाणोदिया, सुमतलाल सुराणा, उमेशकुमार बोहरा, विनोदकुमार डांगी को शामिल किया गया है।

प्रकाशचन्द्र चाणोदिया व नेमीचन्द दलाल को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। पूर्व अध्यक्ष मिश्रीमल कटारिया, महावीरचन्द्र धोका, भंवरलाल चोरड़िया एवं जम्बूकुमार दुगड़ को सलाहकार के रूप में जोड़ा गया है। युवा प्रतिनिधित्व के रूप में धीरजराज नाहर एवं नमित कोठारी का भी समावेश किया गया है।

राजस्थान के केबिनेट मंत्री पटेल ने संतों के किए दर्शन, हुआ सम्मान

बेंगलूरु/दक्षिण भारत । नगर प्रवास पर आए राजस्थान के लूनी के विधायक व राजस्थान में केबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को चामराजपेट जैन स्थानक में विराजित 'राजस्थानी कर्नाटक संघ सर्व समाज गौरव' से अलंकृत श्री नरेशमुनिजी, शालिभद्रजी एवं नवदीक्षित हार्दिकमुनिजी के दर्शन करने का लाभ लिया। संतों ने विधायक से विभिन्न विषयों पर चर्चा कर आशीर्वाद दिया। इसी के साथ लूनी के विधायक ने आंजणा पटेल समाज के नव निर्माणाधीन राजेश्वर भवन के चढ़ावों के कार्यक्रम में श्री राजाराम आंजणा आश्रम के गादीपति महंत श्री दयारामजी की निश्रा में शिरकत की। इस मौके पर विधायक के साथ प्रवासी राजस्थानी कर्नाटक संघ के महामंत्री एवं लूनी के पूर्व सरपंच जवरीलाल लुनावत भी उपस्थित थे। उन्होंने केबिनेट मंत्री जोगाराम से प्रवासियों की ट्रेन संबंधित व अन्य समस्याओं से अवगत कराया। मंत्री पटेल ने युवा वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने व सभ्यता व संस्कार से जोड़ने के प्रयास करने की बात कही। उन्होंने समाज में नशा मुक्ति जागरूकता पर जोर दिया। प्रवासियों की समस्याओं के समाधान करने के लिए उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया। उन्होंने राजस्थान में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी भी दी। जवरीलाल लुनावत व पटेल समाज के लोगों ने जोगाराम पटेल का सम्मान किया।

जेबीएन वी-कनेक्ट महिला व्यवसाय समूह का तृतीय ऑफिस दर्शन कार्यक्रम

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। जीतो जेबीएन वी-कनेक्ट महिला व्यवसाय समूह की सदस्याओं ने ऑफिस दर्शन कार्यक्रम के तहत एचएसआर लेआउट स्थित 'प्राणा लिविंग' लक्ज़री एक्सपीरियंस सेंटर का दौरा किया, जिसमें 38 सदस्याएँ उपस्थित थी। प्राणा लिविंग की मीनू जैन ने अपने प्रतिष्ठान के उत्पादों की जानकारी दी।

कार्यक्रम में जेबीएन वी-कनेक्ट की लीडरशिप टीम रेफरल हेड लीला पितलिया, रेफरल लीड मीनू जैन एवं रेफरल सचिव संगीता जैन का योगदान रहा।

इस मौके पर लेडीज विंग की अध्यक्ष लक्ष्मी बाफना, महामंत्री रक्षा छाजेड़ तथा स्वयम संयोजिका एवं कोषाध्यक्ष तनुजा मेहता उपस्थित थीं।

होली डांडारोपण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

मैसूरु के आईजी सीरवी गैर मण्डल द्वारा पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को केआरएस रोड स्थित आई माता मन्दिर परिसर में होली का डांडा रोपा गया। इस अवसर पर रोली, चंदन और अक्षत आदि से वृक्ष की पूजा की गई। यह होली के प्रतीकात्मक रूप में रोपा जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता हैं। इस मौके पर गैर मण्डल अध्यक्ष रूपाराम राठौड़, उपाध्यक्ष गोपाराम सोलंकी सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे।

महावीर जन्म कल्याणक की तैयारियों के शुभारंभ हेतु संघ-संस्था समन्वय बैठक संपन्न

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जैन युवा संगठन (जेवाईएस) के तत्वावधान में जैन समाज की विभिन्न संघ-संस्थाओं की एक समन्वय बैठक रविवार को बीबीयूएल कॉलेज के प्रांगण में आयोजित हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 31 मार्च को फ्रीडम पार्क में आयोजित होने वाले भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव की तैयारियों का औपचारिक शुभारंभ कर संघ संस्था के बीच समन्वय कर विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की। अध्यक्ष मुकेश सुराणा ने उपस्थित सभी संघ-संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया। उन्होंने संगठन द्वारा जैन समाज की प्रगति, एकता एवं सामाजिक उत्थान हेतु किए जा रहे निरंतर प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। मंत्री सुश्रुत चेलावत ने संगठन की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी तथा महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव हेतु नियुक्त सभी चेयरमैनों का परिचय कराया। ङ्कसेवा ट्रस्ट के मंत्री विनोद नंदावत ने ट्रस्ट द्वारा संचालित जीवन शिक्षा, जीवन रक्षा तथा जीवन संजीवनी योजना की जानकारी दी। स्मृति चिन्ह कमेटी के चेयरमैन अभिषेक कावड़िया ने इस वर्ष के स्मृति चिन्ह (मोमेंटो) की अवधारणा के बारे में बताया। इसके पश्चात सभी उपस्थित अतिथियों, पदाधिकारियों एवं वर्धमान प्रसादी के लाभार्थी 'गुरुपुनवानी प्रोपर्टी' के संजय बैद व विकास बोहरा ने स्मृति चिन्ह का विधिवत लोकार्पण किया। बैठक में चिकपेट आदिनाथ जैन मंदिर के अध्यक्ष गौतम सोलंकी, जैन कॉन्फ्रेंस कर्नाटक के उपाध्यक्ष दिनेश पोखरना तथा दिगंबर समाज कर्नाटक जैन एसोसिएशन के सचिव राजकीर्ति ने अपने विचार व्यक्त किए। संजय बैद ने वर्धमान प्रसादी प्रायोजित करने का अवसर प्रदान करने के लिए संगठन के प्रति आभार व्यक्त किया। सायंकालीन भक्ति संध्या के चेयरमैन दीपक धोका ने 'वीर आगमन' नामक भक्ति संध्या कार्यक्रम की जानकारी दी। संघ-संस्था के चेयरमैन प्रमोद खाबिया ने सभी संस्थाओं के सदस्यों से जन्मोत्सव कार्यक्रम में सहयोग करने की अपील की। सहमंत्री दीपेश धोका ने धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व अध्यक्ष महावीर मुणोत तथा रितेश धोका ने किया। इस अवसर पर संगठन के उपाध्यक्ष रितेश पामेचा, कोषाध्यक्ष विनय गांधी, सेवा ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हेमंत कुमार लोढ़ा सहित अनेक पदाधिकारी, सदस्य तथा समाज के गणमान्यजन उपस्थित थे।

डिजिटल रूप में भी पढ़ें दक्षिण भारत हिन्दी दैनिक www.dakshinbharat.com

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.